

# मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 42 अंक: 33 नई दिल्ली (कुल पेज 16)

14 - 20 अगस्त 2022

मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

वह शेर जिसने क्रान्ति की शुरुआत की.....3  
राज बहादुर गौड़: असाधारण एवं विविध गुणों वाले कम्युनिस्ट.....5  
स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गौरवपूर्ण भूमिका.....8-9

## हमारी आजादी को क्या खतरा है?

चूंकि देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह इतिहास की विडंबना है कि आरएसएस, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहा, अब स्वतंत्रता के लिए हमारे धर्मनिरपेक्ष और समावेशी संघर्ष की विरासत को हथियाने की कोशिश कर रहा है। 75 साल पहले हमारे देश ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया था जब देश के लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए थे। हमारी स्वतंत्रता एक सदी के लंबे समय तक चलने वाले जन-संघर्ष का परिणाम थी, जिसमें राजनीतिक विचारों और विचारधाराओं की कई धाराएँ ब्रिटिश शासन के इस विरोध के संघर्ष में समाहित हो गईं और जनता को ब्रिटिश उत्पीड़न से मुक्त करवाया।

आजादी के लिए हमारा संघर्ष केवल अंग्रेजों को हटाने का आंदोलन नहीं था बल्कि इसमें हमारे देश के भविष्य के लिए एक एजेंडा भी था। सामाजिक सुधारों और हमारे देश को गरीबी और असमानता से मुक्त करने का वह एजेंडा हमारी स्वतंत्रता के लिए लड़ रही प्रमुख विचारधाराओं के बीच एक संवाद का परिणाम था। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे महात्मा गांधी के प्रतिनिधित्व में कांग्रेस पार्टी की नीति और कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्त महात्मा गांधी स्कूल के विचार, कम्युनिस्टों और समाजवादियों और सामाजिक सुधारों के पैरोकारों जिसमें डॉ. अम्बेडकर का काम सबसे अच्छा था, के विचार। इन धाराओं के बीच संवाद और बहस ने उन मूल्यों को जन्म दिया जिन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे संघर्ष को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया और भविष्य के गणतंत्र और राज्य

को एक सुसंगत आकार दिया, जिसके मूल में धर्मनिरपेक्षता और कल्याण था। ये मूल्य आज आरएसएस जैसे एक ऐसे संगठन से खतरे में हैं, जिसने स्वतंत्रता की हमारी लंबी लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई और अंग्रेजों का साथ दिया। यह पहचानने के लिए कि कौन से मूल्य हमारी स्वतंत्रता का गठन करते हैं और क्या खतरे में हैं, हमें इस नापाक संगठन की वैचारिक नींव की जांच करने की आवश्यकता है और यह भी कि यह हमारे संस्थापक नेताओं द्वारा की जाने वाली हर चीज के खिलाफ कैसे है।

जब हमने राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल की, तो भारत को किस प्रकार की सरकार चुननी चाहिए, यह एक काफी चर्चा का विषय था। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 550 से अधिक रियासतें नवोदित गणराज्य के साथ पूरी तरह से एकीकृत थीं और वेस्टमिंस्टर प्रणाली या अमेरिकी प्रणाली के आसपास चर्चा आम थी। संसदीय लोकतंत्र को अधिकांश नेताओं ने प्राथमिकता दी और इसे हमारे संविधान में अपनाया गया। संविधान निर्माताओं विशेषकर डॉ. अम्बेडकर के इस सचेत प्रयास पर स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ पर बोलते हुए राष्ट्रपति के.आर. नारायणन ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि भारत के लिए संसदीय प्रणाली को चुनने में मसौदा समिति ने अधिक स्थिरता के लिए अधिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी, एक ऐसी प्रणाली जिसके तहत सरकार हर दिन निहाई पर होगी। संघ के सीधे प्रभाव के कारण कार्यपालिका द्वारा राज्य की अन्य शाखाओं में किये गए

### डी राजा

अतिक्रमण के कारण सामूहिक जिम्मेदारी का यह विचार आज बहुत दबाव में है। संसद को निरर्थक और निष्प्रभावी बनाने के प्रयास जारी हैं।

आरएसएस, जो अनिवार्य रूप से अलोकतांत्रिक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही प्रतिनिधि लोकतंत्र और संवैधानिक सुरक्षा उपायों से खुश नहीं था। यूरोप के फासीवादियों की आरएसएस द्वारा प्रशंसा और एक नेता सिद्धांत पर उनके जोर ने संगठन को एक लोकतांत्रिक समाज के कामकाज के साथ असंगत बना दिया। बी.एस. मुंजे, आरएसएस के संस्थापक के.बी. हेडगेवार के प्रेरक ने इटली में मुसोलिनी से मुलाकात की और उनसे कहा कि मुझे अवसर पड़ने पर आपके बलिया और फासीवादी संगठन की प्रशंसा में भारत और इंग्लैंड दोनों के सार्वजनिक मंच से अपनी आवाज उठाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं उन्हें शुभकामनाएं और हर सफलता की कामना करता हूँ। आरएसएस अभी भी एक चालकनुवर्तक के नियम का पालन करता है या एक 'सर्वोच्च नेता' की अधीनता का पालन करता है, जिससे वे लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अयोग्य हो जाते हैं। यह लोकतांत्रिक नियमों, मानदंडों और प्रतिनिधित्व के शासन के प्रति आरएसएस द्वारा की गयी अवमानना है। जब हम कहते हैं कि आरएसएस-भाजपा से लोकतंत्र को ही खतरा है, तो उसके ऐसे कीटाणु आरएसएस की नींव और उसके कामकाज में ही देखे जा सकते हैं।

हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के एक आधारभूत मूल्य धर्मनिरपेक्षता के उदाहरण को इस मामले पर विचार करने के लिये लिया जा सकता है। अंग्रेजों के खिलाफ हमारी लड़ाई में हिंदुओं और मुसलमानों ने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। हालांकि, आरएसएस नेताओं और विचारकों के लेखन से यह व्यापक रूप से ज्ञात और स्पष्ट है कि उनका उद्देश्य एक उंच नीच के ढांचे वाला, बहिष्कार करने वाला और भेदभावपूर्ण हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। डॉ. अम्बेडकर ने इस खतरे के बारे में चेतावनी दी थी और कहा था कि यदि हिंदू राज एक तथ्य बन जाता है, तो निस्संदेह, यह इस देश के

लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। संविधान के काफी हिस्से धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक-समर्थक न्याय मॉडल का पालन करते हुए राज्य को समर्पित हैं। यह आरएसएस नेताओं के बहरे कानों तक नहीं पहुंचा। समाज में फूट और कलह के समर्थक दूसरे संघचालक एम. एस. गोलवलकर ने लिखा कि हिंदुस्तान में विदेशी जातियों को या तो हिंदू संस्कृति और भाषा को अपना लेना चाहिए, हिंदू धर्म का सम्मान करना सीखना चाहिए, हिंदू जाति के महिमामंडन के अलावा किसी और विचार का ध्यान नहीं करना चाहिए और संस्कृति, यानी उन्हें हिंदू राष्ट्र और हिंदू जाति में विलीन होने के लिए अपना अलग अस्तित्व खो देना चाहिए, या वे इस देश में रह सकते हैं, पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र के अधीन होकर, वे कुछ भी दावा नहीं कर सकते, वे बिना किसी विशेषाधिकार के, किसी भी प्राथमिकता वाले व्यवहार से दूर रह सकते हैं- यहां तक कि बिना नागरिक अधिकार के।

जब देश अंग्रेजों को भगाने के लिए एकजुट हो रहा था, आरएसएस 'अंदर के दुश्मन' को खोजने में व्यस्त था। हिटलर और मुसोलिनी की बेहद बहिष्कार करने वाली और विभाजनकारी विचारधारा से प्रेरणा लेते हुए, उन्होंने जल्द ही हिंदुओं को अपनी विभाजनकारी राजनीति के पाश में लाने के लिए मुस्लिम को बुराई के रूप में पेश किया। इसने आरएसएस को देश के अतीत के साथ एक खुले युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वे मुसलमानों को बदनाम करने के अपने प्रयासों से उन्हें पीछे धकेलना जारी रखते हैं। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं की आकाशगंगा के बीच, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुगलों को आक्रमणकारी और लुटेरा नहीं कहा, लेकिन आरएसएस के लिए इसे एक लंबे समय तक चलने वाले सांप्रदायिक संघर्ष और कलह के रूप में पेश करना आवश्यक था। सरदार पटेल, जिन्हें आरएसएस अपना बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में अपने ऐतिहासिक अध्यक्षीय भाषण में 'दो शताब्दियों में भारत के निरंतर शोषण' का उल्लेख किया। आरएसएस के लिए, यह शोषण

और दासता सल्तनत और मुगल काल तक फैली हुई है, जबकि अंग्रेजों के प्रति उनकी वफादारी अक्षुण्ण है। देश के लिए दुश्मन ब्रिटिश उपनिवेशवाद था। तो सांप्रदायिक आरएसएस के लिए वह मुसलमान थे। हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, इसकी पहचान करने में अंतर ने ही भारतीय राष्ट्रवाद और आरएसएस के संकीर्ण हिंदुत्व राष्ट्रवाद के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर बना दिया। जैसा कि साफ है, आरएसएस इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी राष्ट्र के खिलाफ था।

जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया गया है, सामाजिक सुधार स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई का अभिन्न अंग था। इस सुधार कार्यक्रम के दो प्रमुख घटक जाति और समाज में महिलाओं की स्थिति से संबंधित थे। मनु के अध्यादेशों से युक्त मनुस्मृति को भारत में जाति व्यवस्था के लिए किसी और ने नहीं बल्कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर ने जिम्मेदार ठहराया। जाति के द्वारा अपमान के विरोध में डॉ. अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति की प्रतियां जलाई थीं। डॉ. अम्बेडकर ने हमारे संविधान के माध्यम से ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्गों के लिए सुरक्षा उपायों के साथ-साथ कड़ा संघर्ष किया और राजनीतिक समानता स्थापित की। हालांकि, ब्राह्मणवादी आरएसएस के लिए, मनुस्मृति समाज में अधिकार और कानून का स्रोत बनी रही और उसके लिए समानता को पचाना असंभव था। हमारे संविधान के अनुमोदन के एक सप्ताह से भी कम समय के बाद, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गनाइजर ने 30 नवंबर 1949 को अफसोस जाहिर किया और कहा कि आज तक उनके (मनु के) कानून, जैसा कि मनुस्मृति में प्रतिपादित किया गया है, दुनिया में सराहना के लिए उत्तेजित रहते हैं और स्वतस्फूर्त भाव से आज्ञा मानने और अनुपालन करने को अपनाते हैं। लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान सभा में दहाड़ते हुए कहा कि 'जातियाँ राष्ट्र-विरोधी हैं। पहली जगह में क्योंकि वे सामाजिक जीवन में अलगाव लाते हैं। वे राष्ट्र-विरोधी हैं क्योंकि वे जातियों के

शेष पेज 15 पर...

### भाकपा ने किया जदयू और भाजपा

#### गठजोड़ में टूट का स्वागत

नई दिल्ली: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भाजपा से गठजोड़ खत्म करने का स्वागत करते हुए 9 अगस्त 2022 को निम्नलिखित बयान जारी:

भाकपा जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भाजपा से नाता तोड़ने का स्वागत किया। वे राज्यपाल से मिले और उन्होंने मुख्यमंत्री के बतौर अपना त्यागपत्र उन्हें सौंप दिया।

पार्टी ने इस घटनाक्रम का स्वागत किया और पार्टी महसूस करती है कि यह हिंदी पट्टी की राजनीति पर एक गंभीर असर छोड़ेगा। इस घटनाक्रम से राजनीतिक ताकतों का एक नया पुनर्गठन होगा, जो 2024 के आम चुनावों में भी दिखाई देगा।

बिहार में भाजपा-नीत सरकार गिरने के बाद भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है। भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतान्त्रिक गठबंधन बिहार में उस समय ढह गया जब जदयू ने भाजपा को अलविदा कह दिया था। हालांकि कई महीनों से भाजपा और जदयू के बीच संघर्ष चल रहा था, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह संघर्ष इतनी तेजी से उनकी सरकार को गिरा देगा। 24 घंटे के भीतर, भाजपा नीत सरकार को बाहर कर दिया गया और महागठबंधन सरकार सत्ता में आई। भारत में राजनीतिक मंथन प्रक्रिया की इस प्रकृति से राजनीतिक विज्ञान के छात्रों को सीखने के लिए अपने स्वयं के सबक हैं।

देश में गहराते सामाजिक-आर्थिक संकट का विस्फोट बिहार में राजनीतिक परिवर्तन में बदल गया। आरएसएस-भाजपा के दिग्गजों ने कभी नहीं सोचा था कि यह अप्रत्याशित रूप से ऐसा मोड़ लाएगा। उनकी महाराष्ट्र की जीत का, जहां उन्होंने शिवसेना में विभाजन किया और अपनी पसंद की सरकार बनाई, जश्न पूरा भी नहीं हुआ था। बिहार में भाजपा को झटका संघ परिवार के लिए झटका है। इस हद तक इसे भाजपा विरोधी ताकतों के लिए प्रोत्साहन माना जा सकता है।

लगभग एक महीने पहले हैदराबाद में आयोजित भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक ने आगामी 40 वर्षों में सत्ता पर आसीन रहने की अपनी श्रेष्ठता की शेखी बघारी गई थी। और भाजपा अध्यक्ष ने खुले तौर पर पार्टी के एकल शासन के लिए अपनी लालसा व्यक्त की। अनंत सत्ता और एकल पार्टी शासन के लिए उनका वैचारिक आधार कोई रहस्य नहीं है। तब भी भाजपा ने जरूरत पड़ने पर अपने इरादों को छिपाने के लिए एक विशेष तरह की चतुराई विकसित की है। उन्हें स्वयं को गठबंधन राजनीति के महारथी के रूप में पेश करने में कोई संकोच नहीं है, जब यह गठबंधन उनकी सुनिश्चित राजनीतिक योजनाओं के अनुरूप होता है। गोवा, मणिपुर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, उन्होंने जरूरतों के आधार पर गठबंधन के साथ सरकार बनाई है और बहुमत हासिल किया है। राजनीतिक नैतिकता के बारे में बहुत अधिक बोलते हैं, वे सत्ता पर कब्जा करने और उससे चिपके रहने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। उनके अलोकतांत्रिक अनैतिक राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संवैधानिक अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों को बड़े पैमाने पर तैनात किया गया है।

## बिहार की राजनीति का बदलता परिदृश्य

गठबंधन राजनीति अपने सहयोगियों से एक लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्कृति की अपेक्षा करता है। भाजपा में अपने फासीवादी राजनीतिक चरित्र के कारण इस संस्कृति का अभाव है। राजनीतिक कारणों से वे भागीदारों के प्रति निष्ठा की शपथ ले सकते हैं। लेकिन उनकी सारी चालें उसकी आत्मा के विरुद्ध होती हैं। भाजपा की राजनीतिक और प्रशासनिक परियोजनाओं में आरएसएस ने हर जगह छिपे एजेंडे को शामिल किया है। भाजपा की साझेदारी वाली किसी भी सरकार को केवल उसी रास्ते से चलना होगा। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने 2000 की शुरुआत से ही, हालांकि छोटे अंतरालों में, इसका अनुभव किया है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति थोड़ी निष्ठा रखने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए,

### संपादकीय

भाजपा के साथ सत्ता साझा करना लगातार संघर्ष का विषय होगा। इन वर्षों के दौरान नीतीश कुमार अपनी चेतना में इस द्वन्द्व से गुजरे होंगे। महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई हैं, जहां भाजपा ने शिवसेना का एक बड़ा हिस्सा सोख लिया है और उन्हें अपनी सहमति के अनुसार तैयार किया है, कहा जा रहा है कि यह जदयू के लिए भाजपा के साथ गठबंधन तोड़ने का तत्काल कारण है।

सामाजिक-राजनीतिक आयामों वाले अन्य कारणों की भी बिहार में नए राजनीतिक विकास को आकार देने में अपनी भूमिका है। इनमें अगिपथ के खिलाफ संघर्ष, जाति गणना का मुद्दा, आदि महत्वपूर्ण हैं। जदयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के इस्तीफे से संभवतः उन्हें नए खतरों के संकेत मिल हों। वहां खबरें हैं कि भाजपा ने महाराष्ट्र मॉडल लागू करने के लिए जदयू के कुछ मंत्रियों और विधायकों से संपर्क किया है।

पटना में नए राजनीतिक विकास के लिए ये सभी एक साथ आए। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण के तुरंत बाद नीतीश कुमार का बयान ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि 2024 नहीं होगा 2014 जैसा। इसमें नरेंद्र मोदी के लिए स्पष्ट चेतावनी है जो 2014 में सत्ता में आए थे और 2024 में सत्ता में बने रहने

की इच्छा रखते हैं।

बिहार के घटनाक्रम की अपनी मजबूती और कमजोरी के साथ अपनी विशिष्ट खासियत है जो की आज के भारत की राजनीति के जैसे है। यह सिद्धांत कि भाजपा अपराजेय है, बिहार में एक बार फिर असफल हो गया है। मोदी की सफलता उनकी नीतियों के गुण-दोष के कारण नहीं बल्कि विपक्ष के बीच फूट के कारण है। आरएसएस-भाजपा के पास इस फूट का इस्तेमाल करने की काबिलियत है। विपक्ष में कई नेताओं की व्यक्तिगत इच्छा और अहंकार भी इस फूट को बनाते हैं जो बदले में केवल भाजपा की मदद करेगी। भारत के लोगों ने साबित कर दिया है कि अगर भाजपा के खिलाफ कोई विश्वसनीय विकल्प होता तो वे उन्हें वोट देना पसंद करेंगे। जीवन की वास्तविकताओं ने उन्हें सिखाया है कि 'अच्छे दिन' के वादे और कुछ नहीं केवल झूठ थे। लोगों को बदलाव की जरूरत है। वे गरीब और अशक्त हैं। लेकिन वे इतने बुद्धिमान हैं कि उचित समय पर उचित निर्णय ले सकते हैं। आज जटिल भारतीय परिस्थितियों में विपक्षी दलों के सामने यह चुनौती है। 2024 की लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि आरएसएस-भाजपा अपनी हिंदुत्व योजनाओं के अनुसार भारत को ढालने के लिए अड़ा हुआ है। हिंदुत्व के समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का कहना है कि यह फासीवाद के भारतीय संस्करण का एक अन्य नाम है। ऐसे दुष्ट शत्रु से लड़ने के लिए, उच्च स्तर के राजनीतिक विश्वास और तैयारी की आवश्यकता है।

भारत की लड़ाई में बिहार एक निर्णायक रंगभूमि है। यह हिन्दी पट्टी के जन मानस की मनोदशा को प्रतिबिंबित करता है। यह ताकत है इस नए गठन की। यह राजनीतिक बदलाव के लिए जनता के संघर्ष का नतीजा नहीं है। जनता की आकांक्षाओं पर आधारित एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम का साकार रूप लेना अभी बाकी है। इसकी अपनी कमजोरियाँ हैं। लेकिन निस्संदेह यह एक सकारात्मक घटना है इसके भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, नई सरकार की कार्यवाही का रास्ता तैयार करने में वाम अपनी विशिष्ट भूमिका निभाएगा। इस नई सरकार के आधार को मजबूत करने के लिए वाम संयुक्त और स्वतंत्र रूप से जनता को लामबंद करेगा और इसे आम जनता के सपनों को पूरा करने के लिए विश्वसनीय बनाएगा।

## कामरेड बालन का निधन पार्टी के लिए अपूर्णनीय क्षति

कामरेड पी.के. बालकृष्णन नायर जिन्हें प्यार से कामरेड बालन कहा जाता था की स्मृति में 4 अगस्त 2022 को भाकपा केंद्रीय मुख्यालय अजय भवन में एक बैठक आयोजित की गई। कामरेड बालन को पार्टी की राष्ट्रीय परिषद, पार्टी के नेताओं, विभिन्न मसलों पर पार्टी के दृष्टिकोण और फैसले, पार्टी इतिहास के बारे में सम्यक जानकारी थी। लगभग पिछले छह दशकों से कॉ. बालन पार्टी के केंद्रीय कार्यालय से संबंधित थे।

कॉमरेड बालन की तस्वीर पर पुष्पांजलि के साथ स्मृति बैठक आरंभ हुई। पार्टी महासचिव डी. राजा के साथ सभा में उपस्थित सभी साथियों ने कामरेड बालन को पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य अनिल राजिमवाले की एक परिचायक टिप्पणी से हुई।

स्मृति बैठक में मौजूद साथियों को

संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव डी. राजा ने कहा कि कामरेड बालन के निधन से पार्टी को अपूर्णनीय क्षति पहुंची है। पार्टी के पुस्तकालय को सुव्यवस्थित रखने, पार्टी के दस्तावेजों को संग्रहित करने में दक्ष, अनुभवी और रूचि लेने वाला उन जैसा व्यक्ति निकट भविष्य में मिलना बहुत कठिन है। कामरेड बालन पार्टी से जुड़े हुए थे और उन्होंने पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेताओं के साथ काम किया था। जरूरत पड़ने पर वे पार्टी से संबंधित जानकारी या दस्तावेज मुहैया कराते थे।

राजा ने कामरेड बालन के साथ जुड़ी अपनी स्मृति को साझा करते हुए कहा कि उन्हें जरूरत पड़ने पर कामरेड बालन से संदर्भ सामग्री और पुस्तकालय से विस्तृत दस्तावेज मिल जाते थे। पार्टी लाइब्रेरी को संघटित, व्यवस्थित करने में और पार्टी लाइब्रेरी को जाने-माने संदर्भ केंद्र के रूप में स्थापित करने में कामरेड बालन की

अहम भूमिका रही है।

अपने जीवन के अंतिम दिनों तक खराब स्वास्थ्य के बावजूद वे नियमित रूप से अजय भवन आते थे।

पार्टी राष्ट्रीय परिषद सचिव अमरजीत कौर ने कामरेड बालन को याद करते हुए कहा कि वे केवल लाइब्रेरियन नहीं थे बल्कि वे पार्टी इतिहास के एनसाइक्लोपीडिया थे। पार्टी स्थापना के बाद अब तक के अंदरूनी घटनाक्रमों पर उनकी स्पष्ट समझ थी। इन सब दुर्लभ गुणों के बावजूद वे काफी साधारण और मिलनसार थे।

कामरेड बालन के पुराने परिचित साथी अनिल राजिमवाले ने बताया कि उन्होंने अजय भवन की लाइब्रेरी को विश्व स्तरीय बनाने में अथक परिश्रम किया था। वे जहां कहीं से भी संभव होता था पठन सामग्री इकट्ठा करते थे और उन्होंने पार्टी के दस्तावेजों का, विभिन्न मुद्दों पर पार्टी के निर्णयों के



दस्तावेजों का कोष गृह तैयार किया। हाल ही में लाइब्रेरी से जुड़ी कृतिका ने कामरेड बालन के साथ अपने अनुभवों को याद करते हुए बताया कि उसे

स्वयं को लाइब्रेरी के संबंध में प्रशिक्षण और लाइब्रेरी को व्यवस्थित रूप से संचालन करने की प्रेरणा और उत्साह कामरेड बालन से मिला है।

9 अगस्त, 1942 को, भारतीय लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासकों को चेतावनी दी कि अब समय आ गया है कि वे देश छोड़ दें। यह महात्मा गांधी द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के लिए जारी किया गया आह्वान था और देश में जनता ने इसका व्यापक रूप से जवाब दिया। महाराष्ट्र के सतारा जिले में लोगों ने इस नारे को सचमुच स्वीकार किया और अगले ही दिन से ब्रिटिश शासन के जुए को उनकी भूमि से उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया।

जैसा कि गांधीजी ने सुझाव दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन अहिंसक तरीके से शुरू हुआ। लेकिन ब्रिटिश शासकों ने सातारा जिले में पांच अलग-अलग स्थानों पर ग्यारह देशभक्तों को मारकर बर्बरता का विकल्प चुना। दमनकारी पुलिस बल, सामंतों और अपराधियों और ठाणों और उनकी स्थानीय सेनाओं के समर्थन से, ब्रिटिश उपनिवेशवादी विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे, लेकिन केवल एक क्षण के लिए, क्योंकि अंग्रेजों का विरोध करने की एक व्यापक पहल समाज की क्रूर राजनीतिक और सामाजिक रूप से दमनकारी सत्ता के ढांचों से मुक्ति के लिए भारतीय लोगों की जबरदस्त इच्छा की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करती थी। दमनकारी उपायों को लंबे समय तक जारी रखना संभव नहीं था। जनता का नेतृत्व वीर नाना पाटिल के द्वारा किया गया, जो लोगों के दिलों में आग जलाते रहे और नए जोश के साथ विद्रोह का नेतृत्व किया। नाना पाटिल का जन्म 3 अगस्त 1900 को हुआ था। उनका निधन 6 दिसंबर 1976 को हुआ।

नाना पाटिल ने अपने पूरे जीवन में भारतीय धरती पर क्रांतिकारी संघर्ष के कई रूपों को विकसित किया।

यह विद्रोह उस समय भारत में हो रहे अन्य आन्दोलनों की तुलना में कहीं अधिक उग्र था। एक ओर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। दूसरी ओर, कई ऐसे भी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के प्रयास किए। संघर्ष के विविध रूप सामने आए। भागलपुर, बलिया, मिदनापुर, कमिला (अब बांग्लादेश में), चंपारण सहित अन्य जगहों पर आंदोलन हो रहे थे।

1930 में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के कपड़ा मजदूरों ने सोलापुर शहर को कुछ दिनों के लिए अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराया था। सोलापुर कम्प्यून का निर्माण मल्लप्पा धनशेठ्ठी, श्रीकृष्ण शारदा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे के नेतृत्व में सोलापुर के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया एक बहुत बड़ा प्रयोग था, जिन्हें बाद में फाँसी पर लटका दिया गया था। सोलापुर कम्प्यून बोल्शेविक क्रांति की

## क्रान्ति सिंह नाना पाटील

# वह शेर जिसने क्रांति की शुरुआत की

प्रतिक्रिया थी और पूरे विश्व को पेरिस कम्प्यून की याद दिलाती थी।

हालाँकि, सोलापुर आंदोलन में देखी गई परिवर्तन की हवाएँ एक अकेले शहर तक सीमित थीं। बाद में, वे पड़ोसी सतारा जिले में एक बड़े तूफान में बदल गईं। नाना पाटिल, एक व्यक्ति के जीवित तार, ने लोगों की मुक्ति की सुप्त इच्छा को एक विशाल शक्ति में सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया। नाना पाटिल ने अगस्त 1943 से मई 1946 तक कम से कम तीन साल की अवधि के लिए लोगों की भागीदारी के साथ एक विशाल ग्रामीण कम्प्यून बनाया। नाना पाटिल का आंदोलन अन्य सभी विद्रोहों से अलग था, जिसमें उन्होंने सैकड़ों गांवों को गुलामी के जुए से मुक्त करने में कामयाबी हासिल की इसके बावजूद कि ब्रिटिश सेना ने उन्हें घेर लिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इस आंदोलन को एक 'प्रति सरकार आंदोलन' के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है एक वैकल्पिक सरकार का आंदोलन।

इस आंदोलन की विशिष्टता को समझने के लिए इस क्षेत्र के इतिहास और भूगोल को समझना होगा। इस क्षेत्र में एक न्यायप्रिय राजा शिवाजी महाराज का शासन देखा था। इसमें क्रमशः महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले के जन्मस्थान कटगुन और नयागांव जैसे गांव भी शामिल थे। 19वीं सदी के महान सुधारक गोपाल गणेश आगरकर का जन्म इसी क्षेत्र के तेंभु में हुआ था। इसने एक ओर मुगलों के खिलाफ शिवाजी के मुक्ति संघर्ष की परंपराओं का प्रतिनिधित्व किया, और दूसरी ओर सामाजिक क्षेत्र में सत्यशोधक आंदोलन के जाति-विरोधी संघर्ष का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ-साथ समाज में सामंती संरचनाओं और दमनकारी जाति व्यवस्था के खिलाफ समाज में एक नई चेतना फैल रही थी। इस क्षेत्र ने कर्मवीर भाऊराव पाटिल द्वारा बनाए गए सामाजिक परिवर्तन और अपने स्कूलों के नेटवर्क के माध्यम से निचली जातियों सहित जनता को शिक्षित करने के उनके जबरदस्त प्रयासों को देखा था। डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर भी अपनी शिक्षा के लिए सतारा में रहे थे। कर्मवीर विठ्ठल रामजी शिंदे ने उसी क्षेत्र में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए जनता को संगठित किया था। कामरेड वी वी चितले भारतीय कम्प्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे के नीचे ग्रामीण जनता को संगठित कर रहे थे। इन सभी आंदोलनों ने मुक्ति आंदोलनों के लिए एक बहुत ही स्थायी माहौल तैयार किया था। नाना पाटिल ने मुक्ति के

लिए संघर्षरत इन सभी शक्तियों के समामेलन का प्रतिनिधित्व किया और क्रांति के युग की शुरुआत की।

प्रति सरकार आंदोलन ने लंबे समय तक लोगों का दमन करने वाली स्थापित सत्ता संस्थानों के खिलाफ आवाज उठाई। इसकी आंदोलन की तुलना में एक ऐसा आंदोलन मिलना दुर्लभ होगा, जिसने ग्रामीण समाज में भारी उथल-पुथल मचाई और प्रमुख सत्ता संरचनाओं और उनकी दमनकारी प्रथाओं को चुनौती दी। इस आंदोलन का उद्देश्य किसानों और श्रमिकों के नेतृत्व में एक नए समाज का निर्माण करना था जिसमें वर्ग, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर कोई शोषण नहीं होगा।

इस क्रांतिकारी आंदोलन द्वारा लाए गए जबरदस्त परिवर्तनों की तुलना उन लोगों से भी की जा सकती है जो यूरोप में पुनर्जागरण लाए थे। नाना पाटिल राष्ट्रीय मुक्ति पर भगत सिंह के निबंध



और यूरोप में हिटलर की फासीवादी ताकतों के खिलाफ होने वाले संघर्ष से प्रेरित थे। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए, उन्हें उन केंद्रों की पहचान करनी होगी जहां ब्रिटिश शासन की शक्ति केंद्रित थी और उन पर प्रहार करना होगा। उन्होंने पुलिस स्टेशनों, क्षेत्र के सामंतों और बदमाशों और अपराधियों की उनकी सेनाओं की पहचान उन तीन शक्ति केंद्रों के रूप में की, जिनके माध्यम से अंग्रेज संचालित होते थे। उन्होंने अनुभवी पहलवान की तरह किया जो जानता था कि इन शक्ति केंद्रों पर हमला किया गया और इन्हें नष्ट कर दिया, तो ब्रिटिश शासन का पतन हो जाएगा। इस प्रकार, वह सैकड़ों गांवों में ब्रिटिश शासन के सत्ता केंद्रों को मिटाने में सफल रहे।

सबसे पहले, उन्होंने युवाओं को एक अनुशासित सेना में संगठित किया, जिसे तूफान सेना कहा जाता है, जो पुलिस स्टेशनों पर हमला करती थी, पुलिसकर्मियों को कैद करती और उनके हथियारों को हथिया लेती। इस संघर्ष की एक और तकनीक थी सरकारी खजाने को लूटना। उस समय, करों के माध्यम से एकत्र की गई बड़ी धनराशि

और सरकारी कर्मचारियों के वेतन के लिए धनराशि ट्रेनों द्वारा भेजी जाती थी। क्रांतिकारियों ने ट्रेनों पर हमला किया, खजाने के बक्से को हथिया लिया गया, और अपनी विद्रोही गतिविधियों को फण्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। इस तरह के हमले धुले जिले से सतारा जिले के कुंडल जैसे छोटे गांवों में फैल गए। क्रांतिकारी रेलवे स्टेशनों को भी जलाते थे। इन गतिविधियों ने ब्रिटिश शासकों को झकझोर कर रख दिया और उनके आत्मविश्वास को कमजोर कर दिया।

इस क्षेत्र के कई सामंत अंग्रेजों के एजेंट के रूप में काम करते थे और अंग्रेजों के सहयोग से गरीब किसानों पर अत्याचार करते थे। मेहनतकश किसानों का यह वर्ग नाना पाटिल की क्रांतिकारी मुक्ति सेना का सिपाही बन गया। उनके हमलों से पहले, सरकारी अधिकारी और पाटिल, देशमुख जैसे अन्य वेतनदार कमजोर हो गये थे। सत्यशोधक आंदोलन ने पहले ही भाट-भिक्षु (ब्राह्मण पुजारियों और उपदेशकों के शासन) को कमजोर कर दिया था।

क्रान्ति सिंह नाना पाटिल की मुक्ति सेना ने साहूकारों के वर्चस्व पर हमलाबोला, जिन्होंने गरीब किसानों को कर्ज के राक्षसी जाल में बांध दिया था। प्रति सरकार आंदोलन ने साहूकारों के घरों पर हमला किया और किसानों को दिए गए ऋण की फाइलों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि किसान इन ऋणों से मुक्त हैं। वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई, जिसने भूमिहीनों के ऋण रद्द करने और भूमि के समान वितरण का आह्वान किया था। प्रति सरकार ने इन मांगों को अपना लिया और उन्हें तुरंत अमल में लाने लगे। इससे किसानों में आत्मविश्वास का संचार हुआ। प्रति सरकार ट्रेनों से लूटे गए सरकारी धन को भी गरीबों में बांटती थी।

इसके अलावा, प्रति सरकार आंदोलन ने एक और बड़ा काम किया जो सामाजिक सुधार से संबंधित था। उन्होंने जाति व्यवस्था के उन्मूलन, अंतर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, शराब निषेध और कैदियों की रिहाई जैसे मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने सक्रिय रूप से कार्यक्रम आयोजित किए जहां वे अपने विचारों को व्यवहार में लाये। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए विभिन्न सांस्कृतिक रूपों का भी विकास किया। उन्होंने युवा कलाकारों, गायकों और अभिनेताओं के समूह बनाए जो विभिन्न जलसा (गीतों और संगीत के साथ संगीत कार्यक्रम)

का प्रदर्शन करते थे, और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच एक नई चेतना पैदा करते थे। यह एक वैकल्पिक सांस्कृतिक मोर्चा बनाने का एक सचेत प्रयास था जिसने पारंपरिक रूपों को चुनौती दी।

इस प्रकार प्रति सरकार एक पूर्ण क्रांति थी जिसने लोगों के जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को अपनाया। यह लोगों से उनकी अपनी भाषा में बात करती थी। उन्होंने संत कवियों की लोकप्रिय भाषा में मार्क्स, लेनिन, फुले और अम्बेडकर के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए और लोगों ने इसे पसंद किया। नतीजतन, भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा एक साथ महीनों तक ब्रिटिश प्रशासन के ग्राम स्तरीय कार्यालय, प्रत्येक चावड़ी पर लहराता रहा।

प्रति सरकार न केवल एक कवि का सपना था, न ही यह एक राह बदलना भर था। यह सही अर्थ में लोगों के शासन का प्रतिनिधित्व करता था। इस आंदोलन की मजबूत नींव इसकी वैज्ञानिक सोच थी। ऐसे कई संगठन थे जो नए राज्य के लिए बनाए गए थे। प्रतिबद्ध सैनिकों की एक सेना थी जो गुरिल्ला युद्ध में दक्ष थी। तब लोगों के उत्थान के लिए खजाना विभाग बनाया गया था। एक आयोजन समिति थी जो लोगों के बीच किए गए कार्यों की निगरानी करती थी। न्यायाधीशों के माध्यम से न्याय देने की एक प्रणाली थी जो मामलों को न्यायसंगत तरीके से संभालती थी। तब बहिरजी नायक समिति थी, लोगों के बीच समाचार फैलाने के लिए एक समिति, संचार के लिए एक समिति, लोगों के लिए स्कूल और उनके कैडर के प्रशिक्षण के लिए।

उनमें सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय तूफान सेना थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं के समूह स्थापित किए, कभी-कभी उनकी संख्या कम होती और कभी-कभी 150 तक होती। समूहों के अपने नेता होते थे। वरिष्ठ स्तर के नेता होते और सबसे ऊपर उनके नियंत्रक होंगे जिन्हें वे 'तानाशाह' कहते। यह उनकी सरकार और प्रशासन की संरचना थी। और इसने पूरी तरह से अच्छा काम किया। इन सभी प्रणालियों के संगठनों के विभिन्न स्तरों पर काम करने के साथ, प्रति सरकार आंदोलन ने लोगों के लिए शासन का एक मॉडल प्रस्तुत किया। यह एक ऐसी प्रणाली बनाने की कवायद थी जिसमें शोषण को मिटाने की कोशिश की गई थी। भारत के आजाद होने के बाद भी नाना पाटिल ने इस परंपरा को जारी रखा।

उन्होंने तेलंगाना संघर्ष में किसानों को हथियार भेजकर उनकी मदद की, जो कम्प्युनिस्ट क्रांति के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का एक शानदार शेष पेज 6 पर...

## आजादी के अमृत को चुनौती देता फासीवाद का जहर

# समाजवाद ही भविष्य है और भविष्य हमारा है

सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय स्वाधीनता के गौरवशाली 75 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।

आजादी के 75 साल पूरा होने का अवसर यकीनन जश्न मनाने का अवसर तो है ही लेकिन उससे भी अधिक यह हमारी आजादी के सामने मौजूद कठिन चुनौतियों को समझने और उनका उसी प्रतिबद्धता के साथ सामना करने हेतु संकल्प लेने का भी है जिस प्रतिबद्धता का परिचय हमारी आजादी की लड़ाई के नायकों ने दिया था।

समूची बीसवीं सदी में दो सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिन्होंने दुनिया भर पर सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया था—सोवियत क्रांति और भारत की आजादी। हम भारतीय कम्युनिस्ट इन दोनों को ही गौरव के साथ याद करते हैं। सोवियत

क्रांति के बाद भारत के स्वाधीनता संग्राम में गुणात्मक परिवर्तन आया था और उसके बाद से यह आम जनता की लड़ाई बन गया था। बेशक महात्मा गांधी का करिश्माई नेतृत्व और कांग्रेस का निरंतर आंदोलन था ही लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आजादी की लड़ाई के हर मोर्चे पर कम्युनिस्ट और क्रांतिकारी बलिदान देने में सबसे आगे की कतारों में शामिल थे। कुछ बानगियाँ यहाँ प्रस्तुत हैं—

—आजादी की लड़ाई के दौरान जितने षड्यंत्र केस चलाये गए जैसे कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर, मेरठ आदि उनमें अधिकांश मुकदमे कम्युनिस्टों पर ही चलाये गए और लंबी सजाएं हुईं। चटगाँव शस्त्रागार मामले पर बनी फिल्म आप लोगों ने देखी ही होगी। ये सब कम्युनिस्ट आंदोलन के गौरवशाली उदाहरण हैं।

### सत्यम सत्येन्द्र पाण्डेय

—आजादी की लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण नारा—इंकलाब जिंदाबाद था और इस नारे के जनक थे मौलाना हसरत मोहानी जोकि 1925 में आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना सम्मेलन के अध्यक्ष थे। ये मौलाना हसरत मोहानी ही थे जिन्होंने सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव खुद कांग्रेस के अधिवेशन में पेश किया था। 1929 में लाहौर में इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने के बरसों पहले कम्युनिस्ट पार्टी अपने स्थापना सम्मेलन में यह प्रस्ताव पेश कर चुकी थी। दअरसल पूर्ण स्वराज्य की माँग ही आजादी की वास्तविक लड़ाई का आगाज थी।

—ये शहीद ए आजम भगतसिंह थे जिन्होंने महज 23 साल की उम्र में सर्वोच्च बलिदान दिया था और जो

खुद को कम्युनिस्ट कहते थे। फाँसी के ठीक पहले वे लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। उन्होंने अपने संगठन के नाम में सोशलिस्ट शब्द जुड़वाया था। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि भगतसिंह के क्रांतिकारी संगठन के लोग जब अपनी कठिन जेलयात्राओं से लौटकर आये तो अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टी में ही शामिल हुए। उनमें से एक और भगतसिंह की जेल भूख हड़ताल के साथी कामरेड अजय घोष तो पार्टी के महासचिव भी बने।

—ये 1936 का वह आग्नेय वर्ष था जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयासों से हुई। इसी साल मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में सज्जाद जहीर के प्रयासों से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। देश के सबसे पुराने विद्यार्थी संगठन आल इंडिया

स्टूडेंट्स फेडरेशन का गठन भी इसी साल हुआ। कुछ साल बाद भारतीय जन नाट्य संघ—इप्टा का भी गठन हो गया। आजादी की लड़ाई में अपनी तरह से महत्वपूर्ण योगदान देने वाले इन महत्वपूर्ण संगठनों की स्थापना के पीछे सीपीआई के तत्कालीन महासचिव कामरेड पीसी जोशी की जबरदस्त भूमिका थी।

—आपको 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की अप्रतिम नायिका अरुणा आसफ अली याद ही होंगी जिन्होंने अगस्त क्रांति मैदान में तिरंगा फहराया था। वे अरुणा आसफ अली आजादी के तुरन्त बाद कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुईं और भारतीय महिला फेडरेशन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अरुणा जी के पति आसफ अली खुद आजादी के दीवाने थे और भगतसिंह और अन्य

शेष पेज 10 पर...

## कारपोरेशनों के लिए वन अधिकार कानून से भीतरघात

श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करते समय भाजपा ने शेखी बघारी थी कि वह आदिवासियों की रक्षक है। परंतु वन अधिकार कानून 2006 में परिवर्तनों का प्रस्ताव कर सरकार ठीक उससे उलटा काम करते हुए कारपोरेट तबके को फायदा और आदिवासियों को नुकसान पहुंचा रही है।

संसद के वर्तमान मानसून सत्र में वन अधिकार कानून 2006 के लिए नए नियम लाने का प्रस्ताव है। इन बदलावों से आदिवासी लोगों के हितों को नुकसान पहुंचेगा। इससे वन संरक्षण को भी नुकसान पहुंचेगा और फायदा किसी को होगा तो वह है सिर्फ कारपोरेट तबका। प्रस्तावित संशोधन सामुदायिक स्वामित्व वाले वनों को निजी खनन एवं फार्मास्युटिकल कंपनियों के हवाले करने के लिए किए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वन अधिकार कानून 2006 में संशोधन के लिए एक बिल ला रहा है। वन अधिकार कानून यूपीए सरकार के दौरान वामपंथी पार्टियों के सक्रिय समर्थन के साथ 2006 में बनाया गया था और उसका मकसद आदिवासी आबादी के हितों की रक्षा करना था। भारत के वनों में लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं जो अपनी बुनियादी रोजी-रोटी के लिए वनों पर सीधे तौर पर निर्भर हैं जबकि लगभग 10 करोड़ लोग उस जमीन पर रहते हैं जिसे वन के तौर पर वर्गीकृत किया

गया है। संक्षेप में कहें तो वनों में रहने वाले आदिवासी हमारे जैविक संसाधनों के असली रक्षक हैं।

नए प्रस्तावित 2022 वन संरक्षण नियमों में पर्यावरण मंत्रालय ने नियम 6(बी) (पप) को जोड़ा है जो निजी पार्टियों को वन भूमि के डायवर्सन को उदार बनाता है। इसमें वन अधिकार कानून 2006 के अनुपालन के बिना वन भूमि का डायवर्सन किया जा सकेगा। इस संशोधन के अनुसार, ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर जिला कलेक्टर प्रति हेक्टेयर नाममात्र की फीस लेकर वन भूमि को निजी पार्टियों को ट्रांसफर कर सकता है। जिसे यह जमीन मिलेगी उसे इस जमीन पर असीमित स्वामित्व प्राप्त हो जाएगा। उसे पेड़ों को काटने का अधिकार मिल जाएगा; वह जमीन के इस्तेमाल, जिसमें भूमिगत खनन और भवनों का निर्माण शामिल है, के लिए प्राप्त जमीन को विकसित करने के लिए वन्य जीवों को विस्थापित कर सकेगा।

वन उत्पादों को लाने-ले जाने एवं उनके पारगमन (ट्रांजिट), लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों के ऊपर लगाए जा सकने वाले शुल्क, बड़े पैमाने पर पेड़ों के काटे जाने की सुविधा और विशाल वन संपदा एवं इमारती लकड़ी के निर्यात आदि को रेगुलेट करने के लिए अंग्रेजी औपनिवेशिक राज के जमाने में 1878 में भारतीय वन कानून बनाया गया था। 1810 से 1950 तक

### डॉ. सोमा माला

की अवधि में वन क्षेत्र लगभग 40 प्रतिशत कम हो गया। इसके फलस्वरूप मौसम के पैटर्न में बदलाव आए और भारतीय उपमहाद्वीप में सूखा और अकाल में वृद्धि हुई। अनेक आदिवासी जातियां इन वनों की सदियों से प्राकृतिक संरक्षक रही हैं। वन क्षेत्र में कमी आने से उनके अनेक पैतृक एवं परंपरागत अधिकार खत्म हो गए और औपनिवेशिक शासकों ने उन्हें वनों से खदेड़ दिया। इससे उनके सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा।

अंग्रेजी शासनकाल में बने वन अधिकार कानून 1878 के कारण आदिवासियों के साथ जो अन्याय होता आया है, उस ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करने और आदिवासी लोगों को सशक्त करने के लिए यूपीए सरकार ने वन अधिकार कानून 2006 बनाया था। वन अधिकार कानून 2006 में वनों में रहने वाले उन आदिवासी समुदायों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के, जो अपनी रोजी-रोटी, निवास एवं सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते आए हैं, अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है।

प्रस्तावित 2022 वन कानून संशोधन बिल की धारा 6(1ए) और (1बी) जैविक विविधता के संबंध में

संयुक्त राष्ट्र की कन्वेंशन और पहुंच एवं लाभ हिस्सेदारी के संबंध में नागोया प्रोटोकॉल (धारा 5), जिसमें भारत एक पक्ष है, की भावना के भी खिलाफ है।

नए 2022 वन संरक्षण नियम पुष्टि करते हैं कि "क्लियर फैलिंग" (यानी पेड़ों को पूर्ण रूपेण काटना) असल में, 40 हेक्टेयर तक और उसके अधिक मात्रा की जमीन से "तमाम प्राकृतिक पेड़-पौधों को हटा देने का काम है"। वर्तमान एनडीए सरकार अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करने के अपने संवैधानिक कर्तव्यों का परित्याग कर रही है।

कारोबार को सुगम बनाने के नाम पर, मंत्रालय ने अब ग्राम सभाओं, राज्य सरकार, विभिन्न (प्रभावित) लोगों की समितियों के स्थान पर एक छोटे से तंत्र की व्यवस्था की है जिसमें चंद पदनामित अधिकारी और मंत्रालय की एक सलाहकार समिति शामिल होगी। वनभूमि डायवर्सिफिकेशन के लिए स्वीकृति के तमाम अधिकार वन-नौकरशाही के हाथ में होंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका है कि वन भूमि के डायवर्सन के लिए ग्रामसभा की अनुमति आवश्यक है। प्रस्तावित संशोधन इस फैसले का भी उल्लंघन करते हैं।

आदिवासी मामला मंत्रालय को भी आपत्ति थी कि वन अधिकार कानून के संबंध में पर्यावरण मंत्रालय को इस

तरह के संशोधन लाने का अधिकार नहीं है। परंतु प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर प्रस्तावित संशोधनों का ड्राफ्ट तैयार किया गया।

भारत के वनों में लगभग 17 हजार किस्म के पेड़-पौधे और अनगिनत जंगली पशु एवं वन्य जीवन पाए जाते हैं। अनेक जीव-वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों एवं कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार वर्तमान वन अधिकार कानून में इस तरह के संशोधनों से वन संरक्षण और जैव-विविधता की दिशा में हो रहे कामों को नुकसान पहुंचेगा और इससे वनों में रहने वाले लोगों के साथ वाणिज्यिक लाभों की हिस्सेदारी के सिद्धांत का भी उल्लंघन होगा।

संसद में इस बिल को लाए जाने से पहले जनता से भी कोई राय नहीं ली गई है। वनों को अक्सर "पृथ्वी के फेफड़ों" के तौर पर भी माना जाता है क्योंकि वन सामान्यतः कार्बनडाई ऑक्साइड को सोखते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। कोई भी कानून जो वनों की कटाई को बढ़ावा दे वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम भी करता है। आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए और वनों की और अधिक कटाई को रोकने के लिए सरकार को इस संशोधन बिल को वापस लेना चाहिए।

## कम्युनिस्ट नेताओं की जीवनी-73

# राज बहादुर गौड़: असाधारण एवं विविध गुणों वाले कम्युनिस्ट

राजबहादुर गौड़ उन नेताओं में थे जो असाधारण एवं विविध गुणों से संपन्न थे। उनका जन्म 21 जुलाई 1918 को गवालीपुरा, हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री राय महबूब राय गौर था और माता का नाम श्रीमती अमरावती गौड़। माता बनारस की थीं। उनके दादा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले से लगभग 1850 के आसपास में हैदराबाद आए और उनके दो छोटे भाई और बहन भी आए। वह गलीबुल मुल्क गालिब जंग की सेवा में शामिल हो गए। राजबहादुर की माता जब वे 3 वर्ष के थे चल बसी। उनकी मृत्यु के 8 साल बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। यह अंतरजातीय विवाह था।

### शिक्षा

राजबहादुर की प्राथमिक शिक्षा तीसरे क्लास से शाली बंदा मिडिल स्कूल में हुई। उसके बाद उसकी पढ़ाई चंद्र घाट गवर्नमेंट हाई स्कूल अंग्रेजी माध्यम में सातवीं क्लास से हुई। राजबहादुर ने मैट्रिक की परीक्षा 1936 में प्रथम श्रेणी में पास की। वह हॉस्टलों में रहा करता था।

राजबहादुर बाद के वर्षों में भी अपने शिक्षकों की बड़ी याद किया करते थे। वह पढ़ने के बड़े शौकीन थे। पढ़ने के लिए वे हैदराबाद के 'आबिडूस' नामक स्थान में स्टेट लाइब्रेरी जाया करते। उन्होंने ढेर सारी किताबें भी खरीदीं और अपने घर में ही एक छोटी सी लाइब्रेरी भी तैयार की।

राजबहादुर ने गालिब और इकबाल से लेकर प्रेमचंद और हसरत मोहनी को पढ़ लिया। इसके अलावा उन्होंने एमएन राय, जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखित 'समाजवाद क्यों', सोशलिस्ट बुक क्लब एवं कम्युनिस्टों के ढेर सारे साहित्य पढ़ लिए। अपने विद्यार्थी दिनों में यह आर्य समाज की मीटिंग में जाने लगे। जब वह नवी क्लास में पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक गणेश उत्सव की सभा में भाग लिया। उसमें खान अब्दुल हकीम कह रहे थे मनुष्य ईश्वर निर्माता जीव है। इसका राजबहादुर पर बड़ा असर पड़ा। उन्होंने बुखारिन का 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' और एमएन राय का 'भौतिकवाद' पढ़ना शुरू किया। इस प्रकार वे समाजवाद की ओर मुड़ने लगे।

स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद राजबहादुर सितंबर 1943 में ओसमानिया यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस कोर्स में भर्ती हो गए। उन्हें 7 रु. की स्कालरशिप भी मिलने लगी। आगे चलकर वे सिटी कालेज में अध्यापक

की नौकरी करने लगे।

### राजनीति में

हैदराबाद कांग्रेस की स्थापना 1938 में की गई। इसकी कार्यकारी समिति की बैठक राज बहादुर के घर में ही हुआ करती। इसका राजबहादुर पर बड़ा असर हुआ। कांग्रेस ने नागरिक अधिकारों और जिम्मेदार सरकार की मांग करते हुए आंदोलन छेड़ दिया। राजबहादुर भी शामिल होना चाहते थे और इस सिलसिले में वे स्वामी रामानंद तीर्थ से मिले भी। 1939 में निजाम के विरुद्ध 'वंदे मातरम आंदोलन' छिड़ गया क्योंकि उसने 'वंदे मातरम' पर पाबंदी लगा दी थी। राजबहादुर इसमें शामिल हो गए।

राजबहादुर ने अपना प्रथम राजनैतिक लेख 1938 में उर्दू दैनिक पयाम में लिखा। उसका विषय था देश की आजादी। 1939 में वे स्टूडेंट्स यूनिनियन में शामिल हो गए। 1940 में वे नागपुर में संपन्न आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) अखिल भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। उनके साथ मखदूम मोहिउद्दीन भी गए। नागपुर में उनकी मुलाकात मुश्ताक, मुखर्जी और बर्धन से हुई। 1941 में पटना में संपन्न एआईएसएफ के सम्मेलन में राज बहादुर शामिल हुए।

1941 में वे उस्मानिया मेडिकल कालेज स्टूडेंट यूनिनियन के उपाध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा यह कालेज की पत्रिका के संपादक भी बनाए गए।

### कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल

1939 में राजबहादुर 'कामरेड्स एसोसिएशन' में शामिल हो गए और जल्द ही कम्युनिस्ट पार्टी में भी। कामरेड्स एसोसिएशन की स्थापना 1938-39 में पार्टी के कई हमदर्दों ने की थी। इनमें शामिल थे सैयद आलम कुंददरी, मखदूम, सैयद इब्राहिम, मानिक लाल गुप्ता, एहसान मिर्जा और नागोराव। इन सब ने मिलकर जल्द ही 'निजाम स्टेट कम्युनिस्ट कमिटी' का गठन किया। राजबहादुर को 1942-43 कामरेड्स एसोसिएशन का सचिव बनाया गया और 1943-44 में अध्यक्ष। मुंबई प्रदेश के गृह मंत्री केएम मुंशी कामरेड एसोसिएशन से बड़े ही नाराज रहा करते राजबहादुर पर जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू का बड़ा प्रभाव पड़ा। वे जल्द ही केएल महिंद्रा के साथ मिलकर आंध्र महासभा में 1940 से काम करने लगे।

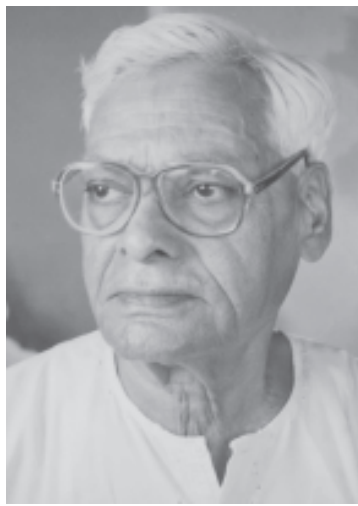
मखदूम मोहिउद्दीन पार्टी के अखबार नेशनल फ्रंट की बिक्री और वितरण

### अनिल राजिमवाले

का काम किया करते। उनकी सहायता राजबहादुर किया करते। मखदूम शहर पार्टी के प्रथम सचिव थे और राजबहादुर सहायक सचिव।

### ट्रेड यूनिनियन आंदोलन में

अपनी कालेज पत्रिका में राजबहादुर में मेडिकल ग्रेजुएट्स को कम वेतन देने का विरोध किया था। इस पर डायरेक्टर आफ मेडिकल सर्विसेज ने आपत्ति जताई। इस प्रकार राजबहादुर आम लोगों की समस्याओं के प्रति बड़े ही संवेदनशील थे। एमबीबीएस कर लेने के बाद उन्होंने आगे प्रैक्टिस नहीं करने और पार्टी का पूरावकती कार्यकर्ता बनने का निर्णय



लिया।

राजबहादुर निजाम स्टेट रेलवे वर्कर्स यूनिनियन, हैदराबाद, गुलबर्गा और नांदेड़ तथा वारंगल के मजदूरों के संगठन कर्ताओं में थे। इसके अलावा उन्होंने अल्विन मेटल और शाहाबाद सीमेंट के मजदूरों को भी संगठित किया।

ऑल हैदराबाद ट्रेड यूनिनियन कांग्रेस का गठन 1945 में मखदूम मोहिउद्दीन, राजबहादुर, केएल महिंद्रा, जवाव रिजवी, गुलाम हैदर तथा अन्य की देखरेख में किया गया। स्थापना के समय से ही राजबहादुर इसके सचिव चुने गए।

उस समय हैदराबाद राज्य में किसी भी प्रकार के ट्रेड यूनिनियन नियम कानून नहीं थे। विश्व युद्ध के बाद कीमतों में भारी वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप हड़तालों की संख्या बढ़ने लगी। इन आंदोलनों में राजबहादुर ने सक्रियता से हिस्सा लिया। वे एमएसके मिल वर्कर्स यूनिनियन गुलबर्गा, डीबीआर मिल्क यूनिनियन तथा अन्य यूनिनियनों के अग्रणी नेता बन गए।

### दमन विरोधी दिवस, 1946

अक्टूबर 16, 1946 को सारे

आंध्र प्रदेश और हैदराबाद राज्य में दमन विरोधी दिवस मनाया गया और मजदूरों ने पूरी हड़ताल कर दी। राजबहादुर, मखदूम मोहिउद्दीन, जवाव रिजवी, अन्य के खिलाफ वारंट जारी किए गए। राजबहादुर और रिजवी अंडर ग्राउंड चले गए लेकिन जल्द ही गिरफ्तार कर लिए गए। कम्युनिस्ट पार्टी पर 15 नवंबर 1946 को पाबंदी लगा दी गई। 7 मई 1948 को राजबहादुर और जवाव रिजवी उस्मानिया अस्पताल से भाग निकले जहां उन्हें हैदराबाद सेंट्रल जेल से इलाज के लिए लाया गया था। इसकी पूरी योजना केएल महिंद्रा, परांजपे, अहमद ने बनाई थी। राजबहादुर 24 अप्रैल 1951 तक अंडर ग्राउंड रहे। उन्हें 24 अप्रैल 1951 को राज कोंडा पहाड़ियों से गिरफ्तार कर लिया गया।

इस बीच पार्टी ने निजाम के राज्य में पीपुल्स कैबिनेट तथा संविधान सभा की मांग पेश की। बाद में पार्टी ने वृहत्तर आंध्र में जनता के शासन का आवाहन किया।

### मुंबई यात्रा और हथियारबंद संघर्ष की तैयारी

1947 में हैदराबाद राज्य में पार्टी ने हथियार उठाने का फैसला किया। यह संघर्ष निजाम के सामंती शासन के खिलाफ था। यह भारत की सरकार के समझाने के लिए राजबहादुर मुंबई गए और पार्टी के महासचिव पीसी जोशी के साथ विचार विमर्श किया। जोशी ने उनका समर्थन किया। वापस आते वक्त राजबहादुर अहमदनगर में एक सार्वजनिक सभा में 'नरसिम्हा रेड्डी' के छद्म नाम से बोले भी। वह विभिन्न पार्टियों के नेताओं से भी मिले। उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त चौधरी और देशपांडे से भी हुई। वे सोलापुर में पार्टी के नेताओं से मिलते हुए विजयवाड़ा वापस लौट आए।

अंडर ग्राउंड रहते हुए ही राजबहादुर ने हैदराबाद शहर पार्टी का सचिव पद संभाला जो अप्रैल में 1948 की बात है। 1950 में यह पद उन्होंने मखदूम को दे दिया और वे हथियारबंद दलों में शामिल होने के लिए राज कोंडा पहाड़ियों में चले गए।

अप्रैल-मई 1948 में निजाम ने वारंट की झूठी घोषणा की। शहर पार्टी कमेटी ने सुल्तान बाजार में एक आम सभा का आयोजन किया जिसके संयोजक बी नरसिम्हा राव थे। राजबहादुर अंडर ग्राउंड से निकले, भाषण दिया, एकाएक बिजली चली

गई और वे एक मकान के बीच से एकाएक गायब हो गए। पुलिस देखती ही रह गई।

### बीटीआर लाइन और अर्थहीन हथियारबंद संघर्ष

कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी अखिल भारतीय कांग्रेस कोलकाता में फरवरी 1948 में हुई। इस कांग्रेस में संकीर्णतावादी दुष्साहसिक लाइन अपनाई गई जो बी.टी.आर. लाइन के नाम से प्रसिद्ध हुई। आरंभ में राजबहादुर ने बीटीआर लाइन का समर्थन किया। इस लाइन के दबाव में और तेलंगाना में पार्टी को सितंबर 1948 में बाद भी हथियारबंद लड़ाई जारी रखने पर मजबूर होना पड़ा। फलस्वरूप पार्टी आम जनता और किसानों से अलग-थलग पड़ गई। किसानों का तथा मध्यम सबको का एक बहुत बड़ा हिस्सा संघर्ष से अलग हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि पार्टी के सशस्त्र दलों को गांव से हटकर जंगलों में शरण लेनी पड़ी। निजाम के भाग जाने के बाद भी हथियारबंद संघर्ष जारी रखना आत्मघाती साबित हुआ।

भारतीय सेनाओं के हैदराबाद राज्य में प्रवेश के बाद भी द्वारा पार्टी द्वारा सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के प्रश्न पर पार्टी में तीखी बहस छिड़ गई। 1950 में बीटीआर पार्टी नेतृत्व से और महासचिव पद से हटा दिए गए। इसके बाद इस प्रश्न पर गंभीर बहस हुई। आखिरकार पार्टी ने सशस्त्र संघर्ष वापस लेने का फैसला किया और प्रथम आम चुनाव में हिस्सा लेने की तैयारियां आरंभ कर दी।

अब राजबहादुर का भी विचार था कि हथियारबंद संघर्ष वापस ले लेना चाहिए और साथ ही निजाम विरोधी संघर्ष की उपलब्धियों को बरकरार रखना चाहिए। पार्टी ने उन्हें राज कोंडा पहाड़ियों और देवरकोंडा जंगल में परिस्थिति का आकलन करने भेजा। यह मार्च-अप्रैल 1951 की बात है। उस समय तक पार्टी के हथियारबंद दस्ते जलगांव भोंगीर तथा राज कुंडा जंगलों के अन्य क्षेत्रों में फैल चुके थे। राजबहादुर के कृष्णमूर्ति तथा अन्य के दलों में काम करने लगे।

राजबहादुर तथा अन्य साथी चार दिवसीय राजनैतिक सैनिक प्रशिक्षण कैंप आयोजित करके लौटने लगे। राजबहादुर कृष्णमूर्ति के साथ नजदीकी पहाड़ियों में चले गए। इस बीच उन्होंने यह जांचने की कोशिश की कि अन्य साथी समय पर निकल गए हैं या नहीं। लेकिन रास्ते में उन्हें कुछ सेना की शेष पेज 14 पर...

## डीपी बदलने से नहीं बल्कि जीडीपी बदलने से देशवासियों का कल्याण होगा

लहेरियासराय, 8 अगस्त 2022: माकपा जिला कार्यालय गुदरी में महागठबंधन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिसको सीपीआई के नेता राजीव कुमार चौधरी, राजद के जिला अध्यक्ष उमेश राय, सीपीआईएम के जिला सचिव अविनाश ठाकुर मंटू, दिलीप भगत, भाकपा माले के जिला सचिव बैजनाथ यादव, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि कल महागठबंधन के राज्यव्यापी आवाहन पर बेतहाशा महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जिला को सूखाग्रस्त जिला घोषित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च व आमसभा ऐतिहासिक रही। इस मार्च और सभा में जिले के कोने-कोने से हजारों लोगों ने शामिल होकर महागठबंधन एकता का परिचय दिया। वहीं कल के कार्यक्रम ने यह साबित कर दिया कि जिले के लोग अब सिर्फ महागठबंधन को ही अपना राजनीतिक विकल्प समझते हैं और लोगों का यह भी मानना है कि वर्तमान वैमनस्यता को महागठबंधन सत्ता में आकर ही ठीक कर पाएगा। इस कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता सहित समस्त जिलावासियों को हम महागठबंधन के नेतृत्व की और से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

वहीं केंद्र सरकार के द्वारा आरएसएस के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें प्लास्टिक और पॉलिस्टर से बने हुए तिरंगा का वितरण

और बिक्री करवाया जा रहा है। हमारे महापुरुषों ने हमेशा से खादी से बने तिरंगा को प्राथमिकता दी है। सरकार को भी चाहिए कि खादी से बने तिरंगे की बिक्री और वितरण करवाया जाए। पूरे देशवासी को पता है कि किस तरह से पॉलिस्टर का सबसे बड़ा उद्योग किस उद्योगपति का है। उसी की मदद से यह सरकार चल रही है। देश जाहिलों के चंगुल में फँसा हुआ है, सत्ता सलामती के लिए तिरंगे तक का अपमान किया और कराया जा रहा है। कानून और संविधान को ताक पर रख दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री सहित इनके सभी मंत्री-संत्री देशवासियों को अपने सोशल मीडिया की डीपी में तिरंगे का फोटो लगाने को कहा जबकि डीपी गोलाकार होती है। तिरंगे का इस्तेमाल कभी भी गोल या तिकोने रूप में करना विजयी विश्व तिरंगा प्यारे का अपमान है और अपराध भी। फ्लैग कोड के निर्देशानुसार तिरंगा हमेशा आयताकार स्वरूप में ही इस्तेमाल होगा। जिसमें निर्देश यह भी है कि इसके उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है। इसलिए जो लोग भी अपनी डीपी या प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा का इस्तेमाल कर रहे हैं वे तिरंगे की शान का अपमान भी कर रहे हैं और अपराध भी। तो फिर आप देख लीजिये कि इनके दिल में तिरंगा कैसा है? तिरंगा महज किसी पार्टी के नेता के झंडे के समतुल्य है नहीं है ये कुर्बानी, बलिदान, एकता, अखंडता, बंधुत्व के प्रतीक है।

फ्लैग कोड के निर्देशानुसार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाये गये

ऊनी/सूती/सिल्क/खादी कपड़े का बना हुआ होना चाहिए। मगर मोदी सरकार ने भारी मात्रा में चाइनीज पॉलिएस्टर का बना तिरंगा आयात करने का ऑर्डर दिया है। इसके खिलाफ महागठबंधन है। हमारे तिरंगे की तरह ही खादी भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महान परंपरा का प्रतीक है। खादी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लोकप्रिय विरोध-प्रदर्शन में गांधीजी द्वारा पूरे देश में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली हथियार थे। इसलिए जिस दिन से राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया, उस दिन से ही हथकरघा में खादी, खादी रेशम और ऊनी कपड़े में राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया। लेकिन पिछले दिसंबर में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज कोड में संशोधन करते हुए आदेश दिया था कि मशीन से बने पॉलिएस्टर झंडे आयात और अधिक से अधिक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यह न केवल हमारी महान राष्ट्रीय विरासत का अपमान है बल्कि खादी उद्योग का भी अपमान है जिसकी जड़ें भारत में गहरी हैं। तथ्य यह है कि जब 1.4 करोड़ खादी श्रमिक उचित मजदूरी और आय के बिना जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं तो पॉलिएस्टर राष्ट्रीय ध्वज को आयात करने का आदेश दिया जाता है, यह साबित करता है कि इस सरकार की नीतियां कितनी जनविरोधी हैं। अगर भारत में 2398 खादी इकाइयों को बड़े पैमाने पर खादी झंडे बनाने का ठेका दिया जाता तो इसका क्षेत्र में बड़ा प्रभाव पड़ता है।

महागठबंधन पूछना चाहती है क्या राष्ट्रध्वज के प्रति देशभक्ति की भावना ऐसे व्यक्ति की जानी चाहिए? एक तरफ पॉलिएस्टर के झंडे आयात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आत्म निर्भर भारत का नाटकीय भाषण दे रहे हैं? इस समय जब देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है तब पॉलिएस्टर झंडों के आयात की अनुमति देने का आदेश राष्ट्रीय ध्वज और इतिहास का

अपमान है। महागठबंधन ध्वज संहिता में संशोधन को बिना शर्त वापसी की मांग करता है।

हर घर तिरंगा तो ठीक है, पर हर घर रोजगार क्यों नहीं? इस तर्ज पर हर घर रोजगार भी चलाना चाहिये। मैं देशभक्ति के भावना का विरोधी नहीं हूँ। लाखों ऐसे लोग हैं जिसके पास झंडा फहराने के लिए अपना घर नहीं है। उसे घर कब मिलेगा? देश के तकरीबन कुल 30 करोड़ घरों में से लगभग 20 करोड़ घरों की छतों पर तिरंगा फहराने की योजना बनाई गयी है। एक झण्डे की कीमत सरकार जो कि 25 रुपए के हिसाब से डाकखाने, राशन कोटे की दुकान और अन्य जगह पर बेच रही है। एक झंडा 25 रुपया और सरकार की योजना के मुताबिक 20 करोड़ घर पर 20 करोड़ झण्डे तो 25 रुपये के हिसाब से 5 अरब रुपये और ये 5 अरब रुपए जनता के जेब से ही लिए जायेंगे और ये 5 अरब रुपए कोई छोटी-मोटी रकम नहीं है, इस रकम से जनता के लिये कई जनहित की कई योजनाएं चलाई जा सकती हैं। पर जब जनता ही फर्जी राष्ट्रवाद की घुड़ी पीला कर उससे सब कुछ छिना चाहती है ये सरकार।

'हर घर तिरंगा' जैसे देशभक्ति वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी स्कूलों में किसी-किसी जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने लिखित और अधिकतर जिले में मौखिक रूप से टीचरों से 40 रुपये प्रति झण्डे के हिसाब से शिक्षकों से वसूली के आदेश दिये गये हैं। इसके एवज में शिक्षक जनता से क्राउड फंडिंग करवा रहे हैं। यानी जनता से वसूली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिला वाराणसी में 1 लाख झण्डे के लिये कुल 40 लाख रुपये की धनराशि दिए गए बैंक खाते में अविलम्ब जमा करने के लिए सरकारी स्कूलों को आदेश जारी कर दिया है। फिर मेहनतकश जनता की जेब से 'राष्ट्र सेवा देशभक्ति' के नाम पर पैसे की वसूली यह सरकार

करेगी।

इसी तरह जम्मू-कश्मीर में तो एक तुगलकी फरमान डुगडुगी पिटवाकर लाउडस्पीकर के माध्यम से अनंतनाग में नगर समिति बिजबेहरा शहर के अधिकारी घोषणा कर रहे थे और दुकानदारों को धमकी दे रहे थे कि 'यदि वे राशि जमा करने में विफल रहे तो उनके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं और परेशानी से बचने के लिये आफिस में 20 रुपये जमा कर देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले लें। इसी तरह जम्मू कश्मीर के मुख्य शिक्षा अधिकारी बड़गाम ने जोन के सभी स्कूलों को 'हर घर तिरंगा' अभियान के लिए प्रति छात्र और स्टाफ सदस्यों के लिए 20 रुपये जमा करने का आदेश जारी किया है। महागठबंधन फर्जी राष्ट्रवाद की आड में देश को कम्पनी राज्य के गिरफ्त जाते देख रही है। आम-आवाम को इससे सचेत रहने का अपील की गयी है।

बिजली बिल विधेयक 2022 को आज मोदी सरकार देश की संसद में 3.00 बजे पेश करेगी। महागठबंधन इस बिजली बिल विधेयक 2022 के प्रारूप को पूरे देश में जलायेगा और इसका पुरजोर विरोध करेगा। बिजली बिल विधेयक 2022 को लागू होने पर देशभर के किसानों, मध्यमवर्ग, छोटे एवं लघु उद्योग को 8 रु. यूनिट बिजली बिल भुगतान करना होगा। किसानों की खेती और महंगी हो जाएगी। छोटे उद्योग, मध्यमवर्ग एवं किसानों के पेट के ऊपर यह बड़ा हमला है।

वहीं बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर महागठबंधन के नेताओं ने कहा कि बिहार सरकार में आरएसएस के प्यादे रहे आरसीपी सिंह ने किस तरह से अकूत संपत्ति अर्जित कर ली है। यह आप जनता के सामने हैं। इसी तरह कई सरकार के मंत्री भी इसमें संलिप्त हैं। कई मंत्रियों ने भी अपनी अकूत संपत्ति जमा की है। इसकी भी जांच होनी चाहिए।

## वह शेर जिसने क्रान्ति की...

पेज 4 से जारी...

उदाहरण है। उन्होंने गोवा के साथ-साथ हैदराबाद की मुक्ति के लिए आंदोलनों में भी मदद की। वह संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के कट्टर नेता थे। वे भाकपा के नेता बने और 1955 में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी चुने गए। वे इतने लोकप्रिय थे कि 1957 में सतारा से और 1967 में मराठवाड़ा क्षेत्र से दूर के एक जिले बीड से भी संसद सदस्य के रूप में चुने गए।

प्रति सरकार आंदोलन की क्रान्ति ने दिग्गज और अग्रणी नेता जैसे जी डी बापू लाड, क्रांतिवीर नागनाथ अन्ना नाइकवाड़ी, बर्दे मास्टर, शेख काका, बाबूजी पाटनकर, डी जी देशपांडे, शांताराम गरुड़ दिये।

इस देश में आज भी शोषण के खिलाफ संघर्ष जारी है। इन प्रयासों के माध्यम से ही उस प्रति सरकार की विचारधारा और व्यवहार की परंपरा जारी है। इस कठिन समय में किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण है। यह नाना पाटिल परंपरा की विरासत है जो आज देश में भयानक प्रतिगामी और तेजी से बढ़ते फासीवादी राज्य की पृष्ठभूमि के खिलाफ संघर्षरत हैं। नाना पाटिल और उनके साथियों की प्रति सरकार ने एक ऐसे सुंदर समाजवादी सपने का प्रतिनिधित्व किया जिसे महाराष्ट्र ने साम्राज्यवाद और शोषण के खिलाफ संघर्ष के समय में देखा था। हमारा समाजवादी आंदोलन इन महान नेताओं के पदचिन्हों पर चलेगा। भारतीय स्वतंत्रता के इस 75वें वर्ष में नाना पाटिल और उनके साथियों को लाल सलाम!

वे लोकसभा में मराठी में बोलने वाले पहले वक्ता थे।

(अखिल भारतीय किसान सभा द्वारा आजादी के संघर्ष के कुछ पन्नों से संकलित)

## पश्चिमी दिल्ली भाकपा का जिला सम्मेलन

नई दिल्ली, 7 अगस्त 2022: भाकपा पश्चिमी दिल्ली जिले का 20वां सम्मेलन सुल्तानपुरी में सम्पन्न हुआ।

इस सम्मेलन का उदघाटन भाकपा राज्य सचिव दिनेश वार्ष्णेय ने किया। अपने उदघाटन भाषण में वार्ष्णेय ने कहा कि देश की गंगा यमुनी तहजीब पर भारी खतरा है। अर्थव्यवस्था में लगातार गिरावट जारी है। नोटबंदी से लेकर जनता सिर्फ महंगाई व बेहद बढ़ती बेरोजगारी के निजाम को ही झेल रही है। मोदी सरकार की नीतियों से सिर्फ पूंजीपतियों की बल्ले बल्ले हो रही है। साम्राज्यवाद एवं पूंजीवाद भारत

व विश्व में सिर्फ मुनाफे की राजनीति चल रहे हैं। सम्मेलन की अध्यक्षता एक अध्यक्षमंडल ने की। अध्यक्षमंडल में बृजभूषण तिवारी, रमा शर्मा व सुरजीत गांधी शामिल थे। सम्मेलन का संचालन शंकर लाल जिला सचिव, राजेश कश्यप, मुकेश कश्यप ने किया।

शंकरलाल जिला सचिव ने रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट पर चर्चा के बाद रिपोर्ट सर्वसम्मति से पास हुई। सार्वजनिक उद्योगों की सेल के विरुद्ध, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुए। सम्मेलन का समापन

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, दिल्ली राज्य परिषद् के पूर्व सचिव व राष्ट्रीय परिषद् के सदस्य धीरेंद्र शर्मा ने किया। सम्मेलन को अजय मालिक, विवेक श्रीवास्तव, राजकुमार ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में 25 सदस्यों की जिला परिषद् चुनी गई तथा 7 सदस्यों का सचिवमंडल-शंकर लाल, राजेश कश्यप, मुकेश कश्यप, रेहाना बेगम, ओमवती, राजेंद्र प्रसाद, राममूर्ति चुना गया। शंकर लाल सचिव व राजेश कश्यप सहसचिव चुने गये। सम्मेलन में 55 डेलीगेटों ने भाग लिया।

आखिरकार, अमरीकी कांग्रेस स्पीकर नैसी पेलोसी ने एक दिन की ताइवान यात्रा की और अमरीकी राष्ट्रपति की सलाह को नजरअंदाज करते हुए ताइवान पर चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का अपमान किया। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति ने उसी समय पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध व्यक्त किया, साथ ही साथ उनके विदेश सचिव ने कहा कि वह अमरीकी नागरिक के रूप में यात्रा कर सकती हैं, इस प्रकार पेलोसी की यात्रा ने अमरीकी प्रशासन के दोहरे स्तर को उजागर किया गया है, जो अंततः ताइवान जलडमरूमध्य में तनाव और अस्थिरता पैदा करना चाहता है। ये सभी प्रयास अमरीकी सैन्य वर्चस्व और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विस्तार की रणनीति का हिस्सा हैं।

1949 में, चियांग काई-शेक के शासन में चीन पर माओ के नेतृत्व में क्रांति की जीत हुई तब चियांग अमरीका के मदद से ताइवान भाग गया और वहाँ से उसने चीन पर शासन करने की कोशिश की। लेकिन 25 अक्टूबर 1971 में, संयुक्त राज्य ने चीन को संयुक्त राज्य में एक मात्र कानूनी प्रतिनिधित्व के रूप में चीन के जनवादी गणराज्य को मान्यता दी। संयुक्त राज्य प्रस्ताव नंबर 2758 में स्पष्ट कहा गया है कि वह "चीन के जनवादी गणराज्य के सभी अधिकार बहाल करने और इसकी सरकार के प्रतिनिधियों को संयुक्त राष्ट्र और इसके सभी संबंधित संगठनों में एकमात्र वैध प्रतिनिधि के

## ताइवान अखंड हिस्सा है 'एक चीन' का

बुद्धिगम जमींदार

रूप में मान्यता प्रदान करने का फैसला करता है और इसके साथ ही महल से चियांग काई-शेक के प्रतिनिधियों को अपदस्थ करता है जिस पर उन्होंने गैर कानूनी रूप से कब्जा कर रखा है"। इस 'एक चीन' की नीति को 1979 में कार्टर सरकार ने भी मान्यता दी थी। हालांकि ताइवान चीन का एक अखंड हिस्सा है, अमरीका अक्सर ताइवान को हथियार बेचने के माध्यम से और छुपे तरीकों से कंपनी व्यापार के माध्यम से ताइवान के संबंध बनाकर चीन और ताइवान के बीच द्वन्द्व पैदा करने की कोशिश करता रहा है।

अपनी यात्रा से कुछ दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिंग पिंग ने राष्ट्रपति बाइडेन को टेलीफोन पर हुई बातचीत में चेतावनी दी थी कि उसकी आने की इच्छा एक आग को छूने जैसी है और आग को बुझाना चाहिए। इस चेतावनी के साथ, पेलोसी ने ताइवान की अपनी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है और अपने एशिया-प्रशांत दौरे के हिस्से के रूप में केवल सिंगापुर, मलेशिया, जापान और दक्षिण कोरिया के नामों की घोषणा की है। लेकिन पेलोसी ने आखिरकार ताइवान का दौरा किया और चीन-अमेरिका संबंधों के साथ-साथ शांति और स्थिरता के लिहाज से एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अस्थिरता पैदा

की।

रोनाल्ड रीगन नामक अमरीकी विमान वाहक पोत ने अपने संबंधित जंगी हवाईजहाज समूह, जहाजों, पनडुब्बियों, गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स और एक क्रूज शिप के साथ सिंगापुर से दो दिन पहले दक्षिण चीन सागर से ताइवान की ओर यात्रा की। इन रोमांचक घटनाओं के बीच, पेलोसी को रात में ताइवान हवाई अड्डे पर बतियों को बंद करने के साथ गहरे अंधेरे में उतरना पड़ा। उनकी यात्रा के जवाब में, चीन ने युद्ध नहीं किया, विमानों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि छह कोनों से ताइवान को समुद्र से घेर कर चार दिवसीय सैन्य अभ्यास किया और साथ ही व्यापार प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय विनिमय वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध घोषित किया और अमरीका के साथ सभी महत्वपूर्ण वार्ता बंद कर दी।

यदि चीन और अमरीका के बीच युद्ध शुरू होता है, तो खतरा है की नाटो देशों और रूस के बीच जारी युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर जाएगा।

इससे पहले, चीनी रक्षा मंत्री लीफेंग ने सिंगापुर में शांगरी-ला संवाद सम्मेलन में अमरीकी अधिकारियों से कहा कि अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश करता है, तो हम

लड़ने (युद्ध) से संकोच नहीं करेंगे और चाहे जो भी हो, लड़ेंगे। चीनी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वे ताइवान के खिलाफ युद्ध करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि चीन की सेना हाथ पर हाथ रखकर नहीं देखेगी।

लेकिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपनी चिंता जता रहा है। इस क्षेत्र के देश बहुत चिंतित हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के 10 सदस्यीय संघ (आसियान) के मंत्रियों की हाल ही में हुई बैठक में फेनोम पेन्ह ने 'उकसाऊ कार्रवाई' के खिलाफ चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि आसियान अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय अस्थिरता से संबंधित है, विशेष रूप से आसियान क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में हाल ही में हुए घटनाक्रमों से, जो इस क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं और अंततः प्रमुख शक्तियों के बीच गलत अनुमान, गंभीर टकराव, खुले संघर्ष और अप्रत्याशित परिणाम पैदा कर सकते हैं। आसियान ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहित सिद्धांतों और दक्षिण पूर्व एशिया (टीएपीसी) में सौहार्द और सहयोग संधि को बनाए रखने के लिए अधिकतम संयम बरतने, उकसाने वाली कार्रवाई से बचने का आह्वान किया है। हम आसियान के सदस्य देश उनकी एक चीन नीति संबंधी समर्थन को दोहराते हैं।

ताइवान एक द्वीप है जिसका घेरा 100 मील से भी कम है। इसे दुनिया

का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय चेक प्वाइंट कहा जाता है। दुनिया के उन्नत सेमीकंडक्टरों में से 92 प्रतिशत यहां निर्मित हैं। कई हाई-टेक उत्पाद जैसे आई-फोन, आई-पैड, उन्नत कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विज्ञान प्रोसेसर आदि। यहां निर्मित होते हैं। अमेरिकी ऑटो उद्योग, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और चालक रहित गाड़ियों के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर यहां बनाए गए हैं।

ऐसा विकास ताइवान और मुख्य भूमि चीन के बीच भाईचारे के संबंधों के कारण संभव था। लेकिन जिस दिन अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के प्रशासन ने 2012 में "पूर्व एशिया की तरफ" क्षेत्रीय रणनीति की घोषणा की थी, उस दिन से ही समस्याएं शुरू हो गईं। अमरीका पहले से ही सैन्य गठबंधन अकुस (एकेयूएस) का हिस्सा है, वह एक नई क्षेत्रीय संरचना तैयार करने की कोशिश कर रहा है जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है और वह इस क्षेत्र में चीन के और कई देशों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए, अपनी सैन्य श्रेष्ठता के लिए ताइवान का उपयोग करना चाहता है।

युद्ध का माहौल तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और ताइवान को चीन का अभिन्न हिस्सा माना जाना चाहिए और ताइवान जलडमरूमध्य में सैन्य तनाव को कम करने के लिए 'एक चीन' के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

## खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी भारतीय गरीबों के बीच कुपोषण को और बढ़ाएगा

ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 (जीएचआई) रिपोर्ट में भारत 116 देशों में से 101वें स्थान पर (ग्लोबल हंगर इंडेक्स भारत का रैंक 116 देशों में 101वां) है। 27.5 के स्कोर के साथ भारत गंभीर स्तर की भूख की श्रेणी में आता है। हम भूख के गंभीर स्तर पर हैं, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। सभी नागरिकों को पोषण सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय योजना की आवश्यकता है।

ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में कुपोषितों की संख्या में पिछले दो साल में 15 करोड़ यानी 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2019 में कुपोषितों की संख्या 61.8 करोड़ थी जबकि 2021 में यह बढ़कर 76.8 करोड़ हो गई।

भूख सूचकांक तीन मानदंडों पर आधारित है, अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति, बाल मृत्यु दर और बाल कुपोषण। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया के कुल कुपोषित लोगों में से एक चौथाई भारत में रहते हैं। यह ऐसे समय में है जब हमारा देश 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के साथ आर्थिक विकास में वैश्विक नेता बनने की आकांक्षा रखता है। कुपोषण को कम करने के लिए देश के सभी नागरिकों को संतुलित

भोजन की आपूर्ति मूलभूत आवश्यकता है। संतुलित आहार का अर्थ है विटामिन और खनिजों के रूप में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और सूक्ष्म पोषक तत्व।

प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल लैंसेट ने एक व्यक्ति की पोषण संबंधी आवश्यकताओं में जाने के लिए एक समिति का गठन किया था। इसमें 232 ग्राम साबुत अनाज, 50 ग्राम कंद या स्टार्च वाली सब्जियां जैसे आलू, 300 ग्राम सब्जियां, 200 ग्राम फल, 250 ग्राम डेयरी भोजन, 250 ग्राम प्रोटीन स्रोत मांस, अंडा, मुरगी के रूप में सेवन करने का सुझाव दिया गया है। मछली, फलियां, मेवा, 50 ग्राम संतृप्त और असंतृप्त तेल 30 ग्राम चीनी। वर्तमान बाजार मूल्य पर इन खाद्य पदार्थों की कीमत प्रति व्यक्ति लगभग 225 रुपये है। इसका मतलब है कि पांच सदस्यों के परिवार को प्रतिदिन 1125 रुपये या केवल भोजन पर 33750 रुपये प्रति माह खर्च करना चाहिए।

एक छोटी आबादी को छोड़कर हमारे लोग इस लक्ष्य से बहुत दूर हैं। 5 किलो अनाज और एक किलो दाल और थोड़ा सा तेल देने की सरकार की योजना पोषण संबंधी आवश्यकताओं

डॉ. अरुण मित्रा

को पूरा नहीं करती है। यह उचित भरण-पोषण के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यह शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक विटामिन और खनिजों जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को बिल्कुल भी पूरा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में 23 करोड़ की आबादी में से 15 करोड़ लोगों के लिए इतना राशन मुफ्त पाने के लिए कतार में लगना पोषण सुरक्षा के मामलों की बेहद निराशाजनक स्थिति का एक प्रक्षेपण है। यह प्रासंगिक है कि लोगों की क्रय क्षमता गरीबी उन्मूलन, पर्याप्त मजदूरी और नागरिकों के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आजीविका के साधन सुनिश्चित करने के माध्यम से बढ़ाई जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी सहित कई आर्थिक विशेषज्ञों ने गरीबी दूर करने के कई उपाय सुझाए हैं।

हाल के आर्थिक सर्वेक्षणों से पता चला है कि हमारी 90 प्रतिशत आबादी प्रति माह 10,000 दस हजार रुपये से कम कमाती है, उनके लिए संतुलित आहार केवल एक सपना है जो वर्तमान परिस्थितियों में सच होता नहीं दिख

रहा है। जरूरी खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने से पेट भरने का खर्चा बढ़ना तय है। दूसरी ओर मजदूरी में गिरावट का रुझान दिख रहा है क्योंकि रोजगार बिना नौकरी की सुरक्षा के और न ही भविष्य निधि या ईएसआई जैसे किसी रोजगार लाभ के ठेके पर काम कर रहा है। लघु उद्योग क्षेत्र जो बड़ी संख्या में लोगों को आजीविका प्रदान करता है, नवउदारवादी आर्थिक नीति के तहत प्राप्त होने वाले अंत में है।

एक युवा वयस्क के लिए कितनी कैलोरी जरूरी है?

एक युवा वयस्क के लिए 2300 कैलोरी और एक स्वस्थ भोजन और कपड़ों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, विभिन्न श्रमिक संगठनों ने इन कैलोरी आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर न्यूनतम मजदूरी की मांग की है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 21000 रुपये प्रति माह की मांग की है। पूरी तरह से निराश करने के लिए, सरकार ने 178 रुपये प्रति दिन या 5340 रुपये प्रति माह के रूप में न्यूनतम वेतन की घोषणा की। यह आंतरिक श्रम मंत्रालय की समिति की 375 रुपये प्रति दिन की सिफारिश के बावजूद है। यह उच्चतम न्यायालय के 650 रुपये प्रति दिन के वेतन की

मांग पर दिए गए फैसले के खिलाफ भी है। समय आधारित कार्य वेतन शुरू करने की सरकार की मंशा आर्थिक रूप से हानिकारक होने के साथ-साथ किसी व्यक्ति की चिकित्सा सलाह और स्वास्थ्य आवश्यकताओं के विरुद्ध भी होगी। हमारे देश में बड़ी संख्या में आबादी असंगठित क्षेत्र में हैं जहां कानूनी फॉर्मूलेशन शायद ही लागू होते हैं। किसान और कृषि श्रमिक जो उत्पादक हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। खेतिहर मजदूरों को आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक भी दोहरे उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। किसानों ने नए कृषि कानूनों का विरोध किया, उन्हें डर था कि इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, बल्कि नागरिकों की खाद्य सुरक्षा से भी समझौता होगा।

यह आवश्यक है कि आवश्यक खाद्य पदार्थ लागत प्रभावी हों और निम्न सामाजिक-आर्थिक समूहों की पहुंच के भीतर हों। सभी वर्गों के लिए मजदूरी को वर्तमान कीमतों पर कैलोरी की जरूरत, संतुलित आहार, कपड़े, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास के अनुसार संशोधित किया जाए। इस संदर्भ में भोजन और अन्य दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर लगाए गए जीएसटी को और कुपोषण को रोकने के लिए वापस लिया जाना चाहिए।

## स्वतंत्रता संघर्ष में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की गौरवपूर्ण भूमिका

यह एक बड़ी विडम्बना है कि देश आज जब अपनी स्वतंत्रता की 75वीं जयंती मना रहा है तो केंद्र में उन सांप्रदायिक, प्रतिक्रियावादी एवं फूटपरस्त ताकतों की सरकार है जिन्होंने स्वतंत्रता के संघर्ष में कभी हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्रता संघर्ष से बिल्कुल अलग रहा। स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने के बजाय उसने देश में सांप्रदायिक फूट पैदा कर अंग्रेज सरकार की मदद ही की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के समूह जिस समय अंग्रेज सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्वतंत्रता आंदोलन से दूर रहा।

यह हमारे इतिहास का एक हिस्सा है कि अपनी तमाम कमजोरियों, दुर्लभताओं और कभी-कभी उसके नेतृत्व की गलतियों के बावजूद, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही थी जिसकी अगुआई में स्वतंत्रता आंदोलन चला और भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। परंतु कांग्रेस की नेतृत्वकारी एवं शानदार भूमिका के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि स्वतंत्रता संघर्ष उसने अकेले ही चलाया। वास्तविकता यह है कि कई पार्टियों, ताकतों, वर्गों एवं संगठनों ने देश की स्वतंत्रता में योगदान किया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उन सबसे अग्रणी पार्टियों में से है जिन्होंने स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने आपको समर्पित कर दिया था। कम्युनिस्ट वास्तव में गर्व कर सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले जो भी लोग पार्टी के सदस्य बने, उन्होंने सभी ने स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लिया; वे सभी स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गर्व है कि उसके सदस्यों ने स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय हिस्सा लिया और अनेक कम्युनिस्टों ने लंबी-लंबी जेल की सजाएं, जीवन भर के लिए देशनिकाला जैसी सजाएं भुगती और कुछ ने तो देश की आजादी के लिए फांसी की सजा भी पाई। 1943 में जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस हुई, उस समय पार्टी की कुल सदस्यता 15,563 थी। उनमें से 695 पार्टी कामरेड जेलों में थे जिनमें से 105 पार्टी कामरेड आजीवन कारावास में थे। पार्टी कांग्रेस में उपस्थित 70 प्रतिशत डेलीगेट एक या उससे अधिक बार जेल जा चुके थे।

भारत के राजनीतिक परिदृश्य में महात्मा गांधी का आना और रूस में

महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति का होना—ये दोनों बातें लगभग एक साथ ही हुईं। इन दो बातों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर जबर्दस्त प्रभाव डाला।

अक्टूबर क्रांति ने दुनिया भर को एक बिजली की तरह रोशन कर दिया। जो देश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, अक्टूबर क्रांति का उनके स्वतंत्रता आंदोलन पर भारी प्रभाव पड़ा। भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा।

प्रसिद्ध मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया कि रूस की बोल्शेविक क्रांति ने भारत की राजनीतिक चेतना को जबर्दस्त प्रेरणा प्रदान की है।

पहले विश्वयुद्ध ने भारत को बुरी तरह प्रभावित किया। युद्ध के लिए सरकार ने भारी टैक्स लगाए, महंगाई बहुत अधिक थी, मुनाफाखोरी चल रही थी और बेहद बदहाली और गरीबी के हालात थे। इससे जनता में व्यापक आक्रोश था। किसानों और मजदूरों के स्वतःस्फूर्त संघर्ष सामने आ रहे थे। देश में बैचैनी का आलम था। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसमें गांधीजी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया और जनता से उसको अभूतपूर्व समर्थन मिला।

कम्युनिस्टों को श्रेय जाता है कि अंग्रेजी दासता से पूरी आजादी के सवाल को उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्रीय मंच पर स्थापित किया। जिस समय कांग्रेस "होम रूल", "डोमिनियन स्टेटस", "उत्तरदायी सरकार" और अस्पष्ट तरीके से "स्वराज" आदि की बातें कर रही थी, कम्युनिस्टों ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्ण स्वतंत्रता का अर्थ है अंग्रेजों से पूरी तरह छुटकारा।

उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन (दिसंबर 1921) में नवगठित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (जिसका गठन 7 अक्टूबर 1920 को ताशकंद में हुआ था) ने एम.एन. राय एवं अरुण मुखर्जी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र हजारों की संख्या में कांग्रेस अधिवेशन में बांटा। उसकी मुख्य मांगें थी: भारत को पूर्ण स्वतंत्रता और एक लोकतांत्रिक गणतंत्र, सामंतवाद विरोधी बुनियादी कृषि सुधार और मजदूर वर्ग को ट्रेड यूनियन अधिकार।

अहमदाबाद कांग्रेस में हसरत मोहानी (जिन्होंने बाद में 26 दिसंबर 1926 को कानपुर में कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस की स्वागत समिति की अध्यक्षता की थी) ने एक प्रस्ताव रखा

### आर.एस. यादव

जिसमें उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और "स्वराज की परिभाषा सभी विदेशी नियंत्रणों से मुक्त पूर्ण स्वतंत्रता" के तौर पर की।

यह भी उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस में जिस समय महात्मा गांधी मोहानी द्वारा प्रस्तुत स्वराज की परिभाषा के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकार न करने के लिए कह रहे थे उस समय कुछ कम्युनिस्ट पहले ही गिरफ्तार थे और उन पर इस आरोप में मुकदमा चल रहा था कि उन्होंने भारत से अंग्रेज बादशाहत को उखाड़ फेंकने की साजिश की। 10 अक्टूबर 1921 यानी अहमदाबाद कांग्रेस से दो महीने पहले कम्युनिस्टों के खिलाफ पेशावर षडयंत्र मुकदमा शुरू हो गया था।

1921 से 1927 के बीच कम्युनिस्टों के खिलाफ, एक नहीं, दो नहीं, पांच मुकदमों चलाए गए जिन्हें पेशावर षडयंत्र मुकदमों के नाम से जाना जाता है। इन मुकदमों में आरोप था कि उन्होंने भारत से अंग्रेज बादशाहत को उखाड़ फेंकने की साजिश की।

1920 के प्रारंभ में भारत में कम्युनिस्ट बहुत ही कम संख्या में थे। उनकी संख्या सैंकड़ों में भी नहीं थी। उनकी संख्या कम होने के बावजूद अंग्रेजों की नींद हराम थी। उन्हें डर लग रहा था कि कम्युनिस्ट भारत में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस डर ने उन्हें कम्युनिस्टों के खिलाफ एक के बाद दूसरा, कई मुकदमों चलाने के लिए प्रेरित किया। जिस समय पेशावर षडयंत्र मुकदमे चल रहे थे उन्होंने कानपुर षडयंत्र के नाम पर चार कम्युनिस्टों—मुजफ्फर अहमद, एस.ए. डांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता के खिलाफ एक मुकदमा और शुरू कर दिया।

26 दिसंबर 1926 को देशभर के कम्युनिस्टों की कानपुर में एक कॉन्फ्रेंस हुई जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कॉन्फ्रेंस बन गई। इस कॉन्फ्रेंस की स्वागत समिति के अध्यक्ष सिंगारवेलु ने पार्टी के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए कहा: "कम्युनिज्म का आंदोलन किसानों और मजदूरों का आंदोलन है, और पार्टी का तात्कालिक लक्ष्य "स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता" हासिल करना है"।

1928 तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रमुख औद्योगिक शहरों में मजदूर वर्ग के बीच अच्छी-खासी

ताकत बना ली थी। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर भी एक वामपंथी खेमा उभरना शुरू हो गया था। कांग्रेस के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि कांग्रेस के वामपंथी खेमे के साथ नजदीकी के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन (1927) में जोर दिया कि कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य तय करे।

मद्रास अधिवेशन का यह एक रोचक प्रसंग है कि जब बंबई के कम्युनिस्ट नेता के.एन. जोगलेकर ने एक पंक्ति का यह प्रस्ताव रखा कि "भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करना होना चाहिए", तो वह और अन्य कम्युनिस्ट उस समय अत्यंत खुशी के साथ यह देखकर चकित रह गए जब जवाहरलाल नेहरू इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए सामने आ गए। बाद में यह प्रस्ताव पारित हो गया।

1928 में कांग्रेस के कोलकत्ता अधिवेशन में कम्युनिस्टों ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस ने गांधीजी द्वारा पेश मुख्य प्रस्ताव में एक जैसे ही संशोधन पेश किए। इन संशोधनों में मांग की गई थी कि मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस के जिस लक्ष्य का अनुमोदन किया गया था, कांग्रेस उसका पालन करे। कम्युनिस्टों और अन्य वामपंथी राष्ट्रवादियों ने इस संशोधन का समर्थन किया। परंतु गांधीजी के हस्तक्षेप और समूचे दक्षिणपंथी नेतृत्व के विरोध के कारण यह प्रस्ताव कुछ मतों से पराजित हो गया। अगले दिन कम्युनिस्टों के नेतृत्व में 50 हजार मजदूर, कांग्रेस के नेतृत्व में 50 हजार मजदूर, कांग्रेस के राष्ट्रपति मोतीलाल नेहरू से इजाजत लेकर कांग्रेस पंडाल में घुस गए। वहां पर उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया और फिर वहां से चले गए।

निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 1921 से ही कांग्रेस के हर अधिवेशन में कम्युनिस्ट पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य तय करने के लिए जो कोशिशें कर रहे थे और जिसके लिए कलकत्ता अधिवेशन में मजदूर वर्ग ने दबाव डाला, उसका कांग्रेस नेतृत्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और कांग्रेस के अगले अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन (दिसंबर 1929) में कांग्रेस ने घोषणा की कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1 के शब्द "स्वराज" का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता होगा और कांग्रेस आशा

करती है कि अब सभी कांग्रेसजन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अपने आपको समर्पित करेंगे।

अंग्रेज सरकार स्वतंत्रता आंदोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका पर गहरा नोट ले रही थी। उसे इस बात की खासतौर पर चिंता थी कि कम्युनिस्ट मजदूर वर्ग को लामबंद कर रहे हैं। कम्युनिस्टों के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में मजदूर भारत के विभिन्न हिस्सों में न केवल आर्थिक मांगें उठा रहे थे और उनके लिए संघर्ष कर रहे थे बल्कि उन्होंने राजनीतिक मांगें भी उठाना शुरू कर दिया था और उन्होंने राजनीतिक कार्रवाईयों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था।

20 मार्च 1929 को सरकार ने अनेक कम्युनिस्टों और मजदूर नेताओं को मेरठ षडयंत्र मुकदमें में गिरफ्तार कर लिया। देशभर में 31 लोग गिरफ्तार किए गए। एक व्यक्ति को बाद में गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबर्दस्त प्रचार मिला। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. अंसारी आदि कांग्रेस के बड़े नेता मेरठ जेल में बंद कम्युनिस्ट एवं मजदूर नेताओं से मिलने गए और उन्हें अपना समर्थन दिया।

कम्युनिस्ट और मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर सरकार उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से अलग नहीं कर सकी जो कि उसका इरादा था। परंतु इससे वह कम्युनिस्ट और मजदूर आंदोलन को नेतृत्वविहीन करने में काफी हद तक कामयाब हुए जिसका आगामी वर्षों में गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

कांग्रेस वर्किंग कमेटी (14-16 फरवरी 1930, साबरमती) ने "सविनय अवज्ञा आंदोलन" शुरू करने का आह्वान किया। उसके बाद गांधीजी ने मार्च 1930 में सुप्रसिद्ध दांडी मार्च किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन को अभूतपूर्व जनसमर्थन मिला। परंतु साथ ही भारी दमनचक्र भी शुरू हो गया।

1930 में जब गांधीजी कम्युनिस्ट नेताओं से मिलने मेरठ जेल गए थे तो कम्युनिस्ट एवं मजदूर नेताओं ने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपने पूर्ण सहयोग एवं समर्थन का भरोसा दिलाया था। परंतु जेल से बाहर कुछ कम्युनिस्टों ने इस आंदोलन का "बुर्जुआ" सुधारवादी आंदोलन कहकर मजाक उड़ाया। इसके लिए काफी बड़ी हद तक कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की भी जिम्मेदारी है जिसने कांग्रेस नेतृत्व के संबंध में गलत समझ बनाई थी।



कांग्रेस के कराची अधिवेशन (अप्रैल 1931) में कम्युनिस्टों ने अपना “ड्राफ्ट प्लेटफार्म ऑफ ऐक्शन” वितरित किया। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा गया कि कम्युनिस्ट उसमें हिस्सा लें या न लें। कुछ कम्युनिस्टों ने हिस्सा लिया और वे जेल गए। परंतु यह मानना होगा कि संकीर्णवादी समझ, इस दस्तावेज में आंदोलन में शामिल होने के आह्वान के अभाव, और कांग्रेस नेतृत्व-खासतौर पर उसके वामपंथी धड़े के प्रति नकारात्मक रवैये के कारण सामान्य तौर पर कम्युनिस्ट इस आंदोलन से अलग रहे।

परंतु यह समझना गलत होगा कि 1930 और 1933 (जब कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी लाईन को दुरुस्त करना शुरू किया) के बीच कुछ नहीं किया गया। पार्टी मजदूरों के बीच सक्रिय काम करती रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में पार्टी के गलत दृष्टिकोण के बावजूद कुछ कम्युनिस्टों ने आंदोलन में हिस्सा लिया।

जब मेरठ के कैदी एक के बाद दूसरा जेल से बाहर आना शुरू हो गए तो पार्टी ने बिखरे हुए कम्युनिस्टों को एकजुट करने और पार्टी को एक सुगठित पार्टी बनाने की दिशा में काम शुरू किया। पिछले वर्षों में पार्टी ने जिस हानिकारक संकीर्ण लाईन को अपनाया था उसमें चौतरफा सुधार करने का काम हाथ में लिया गया।

ट्रेड यूनियन एकता को फिर से बहाल किया गया और पार्टी ने कांग्रेस के इर्दगिर्द यूनाइटेड नेशनल फ्रंट बनाने की दिशा में कोशिश की। पार्टी को एकजुट किया गया, अखिल भारतीय स्तर पर संगठित किया गया और पार्टी के कामकाज में समन्वय और संगठन के लिए एक अखिल भारतीय पेपर शुरू किया गया। पार्टी ने कांग्रेस के अंदर बेहतर तरीके से अपने आपको संगठित किया, और कांग्रेस के अंदर की वामपंथी ताकतों के साथ तालमेल बनाया। पार्टी ने एकता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए जोरदार संघर्ष चलाने पर जोर दिया।

1935 के अंत में दिमित्रोव रिपोर्ट भारत के कम्युनिस्टों के पास पहुंची। उनके बीच पुनर्विचार शुरू हो गया। अधिकारी, घाटे और मिरजकर को एक के बाद दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद सोमनाथ लाहिड़ी को पार्टी महासचिव चुन लिया गया था। उन्होंने दिमित्रोव रिपोर्ट और दत्त-ब्रेडले थीसिस के आधार पर एक नया राजनीतिक थीसिस तैयार किया। पार्टी में एक नया मोड़ आया।

कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन (अप्रैल 1936) में सक्रिय हिस्सा लिया। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के राष्ट्रपति थे। वह अपनी पत्नी कमला की मृत्यु के बाद हाल ही में यूरोप से लौटे थे। यूरोप में उन्होंने रजनी पाम दत्त समेत अनेक कम्युनिस्ट नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने दिमित्रोव रिपोर्ट को भी देखा था। जाहिर है इसका उनपर बड़ा असर पड़ा जो उनके भाषण में नजर आया जब उन्होंने कहा कि “मैं इस बात का कायल हूँ कि भारत की समस्याओं के समाधान की कुंजी समाजवाद में है”। कांग्रेस अधिवेशन में शामिल कम्युनिस्टों ने उनके भाषण का समर्थन किया।

1938 में कम्युनिस्टों ने सुभाषचंद्र बोस को फिर से राष्ट्रपति बनाए जाने की दिशा में काम किया। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष कांग्रेस के राष्ट्रपति बन गए। परंतु उन्हें सही तौर पर काम करने नहीं दिया गया और निराश होकर सुभाषचंद्र बोस ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया।

सुभाषचंद्र बोस के फिर से राष्ट्रपति चुने जाने से देश में बढ़ते रेडिकलाइजेशन का पता चलता था। यह पहली बार हुआ कि बंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनावों में डॉ. अधिकारी को सबसे अधिक मत पड़े और बंबई नगरपालिका के चुनावों में भी चार कम्युनिस्टों नेताओं को सबसे अधिक मत पड़े थे।

सितंबर 1939 में दूसरा महायुद्ध युद्ध शुरू हो गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो ने घोषणा की कि भारत की जनता का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए युद्ध संकट का क्रांतिकारी उपयोग करे।

सरकार ने दमनचक्र चला दिया। देशभर में कम्युनिस्टों और रेडिकल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। होम मेम्बर रेजिनाल्ड मैक्सवेल ने बताया कि जिन 700 लोगों को बिना ट्रायल गिरफ्तार किया गया है उनमें से लगभग 480, लगभग बिना किसी अपवाद, जाने-पहचाने कम्युनिस्ट हैं या कम्युनिस्ट कार्यक्रम के सक्रिय समर्थक हैं।

22 जून 1941 को जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। यह युद्ध में एक नया मोड़ था। कांग्रेस ने नोट किया कि युद्ध का चरित्र बदल गया है। कांग्रेस ने सोवियत संघ, चीन और फासिस्ट ताकतों द्वारा गुलाम बनाए गए देशों के साथ अपनी एकजुटता और युद्ध को सशर्त समर्थन की घोषणा की और “राष्ट्रीय रक्षा के लिए राष्ट्रीय सरकार” की

मांग की। सरकार ने मांग को नामंजूर कर दिया।

7-8 अगस्त 1942 को बंबई में एआईसीसी की बैठक में सुप्रसिद्ध “भारत छोड़ो” प्रस्ताव को पारित किया-परंतु बिना किसी योजना या तैयारी के। सरकार ने तुरंत ही कांग्रेस के नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया। देश की जनता ने इस पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया की। हर कहीं स्वतःस्फूर्त विरोध शुरू हो गया। अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ और देश की स्वतंत्रता के लिए लगभग स्वतःस्फूर्त जनविद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो गयी। सरकार ने निर्मम दमन शुरू कर दिया। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार, 9 अगस्त से 31 अगस्त 1942 तक 60,229 लोग गिरफ्तार, 18,000 नजरबंद कर लिए गए थे और सेना और पुलिस की फायरिंग में 940 लोग मारे जा चुके थे।

अनेक कम्युनिस्ट नेता देवली नजरबंदी कैम्प में बंद थे। पार्टी पर प्रतिबंध था। पार्टी केंद्र भूमिगत रहकर काम कर रहा था। दिसंबर 1941 में देवली कैम्प के कामरेडों ने एक दस्तोवज भेजा जिसमें पार्टी की लाईन को बदलने का सुझाव था। फरवरी 1941 में पोलित ब्यूरो ने एक प्रस्ताव में कहा: “जनयुद्ध में भारत की जनता को एक जनभूमिका का निर्वाह करना चाहिए”। जुलाई 1942 में सरकार ने पार्टी से प्रतिबंध हटा लिया।

पार्टी ने अत्यंत उत्साह के साथ युद्ध के प्रगतिशील चरित्र और सोवियत संघ की मुक्तिकारी भूमिका का प्रचार किया, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों और कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ उसके मिथ्या निंदा अभियान को बेनकाब किया।

परंतु पार्टी ने जनयुद्ध की नीति को अंशतः यांत्रिक तरीके से लागू किया और फासिस्ट विरोधी युद्ध को बिना शर्त समर्थन की समझ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यदायित्व को सही तरीके से इंटीग्रेट करने में विफल रही। पार्टी ने संघर्ष विरोधी और हड़ताल विरोधी लाईन अपनाई।

इस लाईन का नतीजा पार्टी के अलग-थलग पड़ने, पार्टी की पोलीशन कमजोर होने और यहां तक कि उसके जनआधारों में भी विभाजन के रूप में निकला। इससे कांग्रेस और समाजवादी नेताओं को कम्युनिस्टों पर देशद्रोही और ब्रिटिश एजेंट होने जैसे लाछन लगाने का हथियार मिला।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने युद्ध प्रयासों का समर्थन किया परंतु उसने देश की स्वतंत्रता की अपनी मांग पर कभी समझौता नहीं किया। इस नए

अवसर पर पार्टी ने स्वतंत्रता संघर्ष की विशेष रणनीति अर्थात् “राष्ट्रीय रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सरकार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता” के लिए सही तौर पर काम किया। परंतु भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया। परंतु ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्टी ने स्वतंत्रता आंदोलन से स्वयं को अलग किया हो।

9 मई को बर्लिन के पतन के बाद दूसरा महायुद्ध समाप्त हो गया। इसका राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों और उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलनों पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा। दुनियाभर में समाजवादी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलनों में एक जबर्दस्त उभार आया। युद्धोत्तर इस जनउभार को भारत में भी एक रफ्तार मिली। देशभर में हड़तालों का तांता लग गया। विभिन्न शहरों में सरकार विरोधी प्रदर्शन होने लगे। 22 नवंबर 1945 को कलकत्ता में जबर्दस्त प्रदर्शन हुए। सड़कों पर बैरिकेड लगे। पुलिस और सेना के साथ प्रदर्शनकारियों के टकराव हुए। मजदूर वर्ग की हड़तालों के अलावा किसानों के आंदोलन ने भी तेजी आ गई जैसे कि इसी दौर में तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष, बंगाल में तैभागा आंदोलन, मोंटगुमरी में काश्तकारों का संघर्ष, बिहार के किसानों का बख्शत आंदोलन, वर्ली, तंजावुर, उन्नाव एवं मलाबार क्षेत्र में किसानों के आंदोलन हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता इन संघर्षों में सक्रिय हिस्सा ले रहे थे। असल में, इनमें से अधिकांश संघर्षों की पहल और नेतृत्व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ही की। मजदूरों और किसानों की मांगों के साथ-साथ इन संघर्षों में देश की आजादी की मांग भी उठती रही। संघर्षों की यह प्रचंड लहर तो चल रही ही रही थी कि 1946 में बंबई में वायुसेना के कुछ लोगों ने हड़ताल

कर दी; चंद दिनों के बाद शाही भारतीय नौसेना ने भी हड़ताल कर दी जिसने गदर जैसा रूप ले लिया। हड़ताली नौसेना ने अपने जहाज पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे लगा दिए। हड़ताल थाना, कराची, कलकत्ता और विशाखापट्टनम तक पहुंच गई। 21 फरवरी तक लगभग समूची शाही भारतीय नौसेना हड़ताल में शरीक हो गई। अंग्रेज फौज बुलाई गई। नौसेना के हड़ताली लोगों और अंग्रेज फौज के बीच गोलियां चली। 21 फरवरी को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने शाही भारतीय नौसेना के लोगों के समर्थन में बंबई में हड़ताल का आह्वान किया। भारी संख्या में मजदूर, छात्र और जनता के अन्य लोग सड़कों पर उतर पड़े; जगह-जगह एकजुटता प्रदर्शन हुए। अनेक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस/सेना के बीच टकराव हुए। 23 और 24 फरवरी को बंबई में पुलिस/सेना ने फायरिंग की जिसमें 270 लोग मारे गए। 1700 लोग जख्मी हो गए। यह एक ऐतिहासिक महत्व की बात है कि सेना, नौसेना और वायु सेना के क्रांतिकारी लोगों के साथ मजदूर वर्ग कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही वह पार्टी है जिसने इस ऐतिहासिक एकता को बनाया, भले ही वह थोड़े ही समय के लिए रही।

युद्ध के बाद के समय के इस तरह के जबर्दस्त जनउभार ने ब्रिटिश सरकार का विश्वास डिगा दिया। उसे समझ आ गया कि भारत में वह अब अधिक समय तक नहीं टिक सकते। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गर्व है कि उसने देश के स्वतंत्रता संघर्ष में एक ऐतिहासिक एवं गौरवपूर्ण भूमिका निभायी।

## खिलाड़ियों को भाकपा की बधाई

नई दिल्ली, 9 अगस्त 2022: राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा बेहतर

प्रदर्शन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने खिलाड़ियों के प्रशिक्षक एवं खिलाड़ियों को शानदार सफलता के लिए बधाई दी है।

राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक जीतने पर भाकपा के राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान ने कहा कि खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों के निरंतर प्रयास और मेहनत का ही परिणाम है।

देश को इन खिलाड़ियों पर गर्व है। प्रशिक्षकों के अतिरिक्त भाकपा ने स्पोर्ट्स ऑथारिटी ऑफ इंडिया (साई) को भी बधाई दी कि वह पिछले एक दशक से खेलों के स्तरों को सुधारने में विशेष ध्यान दे रहे हैं।

नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को उत्साहित और प्रशिक्षित करने के लिए उनकी भूमिका प्रशंसनीय है। देश आशा करता है कि हमारे खिलाड़ी आगामी आलंपिक में राष्ट्रमंडल खेलों में मिली सफलता से प्रभावित होकर और बेहतर प्रदर्शन करेंगे।

## बिलासपुर में मना आदिवासी विश्व दिवस और भारत छोड़ो की वर्षगांठ

बिलासपुर: 9 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ एवं विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सम्बद्ध जनसंगठनों ने नेहरू चौक पर दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक पॉपुलर की अध्यक्षता में धरना-प्रदर्शन एवं आमसभा का आयोजन किया।

सर्वप्रथम आमसभा को नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रान्त शर्मा ने संबोधित करते हुये देश में बढ़ती बेरोजगारी नौजवानों के भविष्य के लिये खतरनाक बताया तथा साथ ही सरकारी भर्तियों को बंद कर संविदा भर्ती किये जाने पर केंद्र व राज्य सरकारों की निंदा की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा सेना में संविदा भर्ती 'अग्निवीर' की कड़ी आलोचना कर स्थायी भर्ती करने की मांग की।

भाकपा माले के नेता लल्लन सिंह ने केंद्र सरकार को महंगाई बढ़ाने का जिम्मेदार ठहराते हुये जीवन उपयोगी आवश्यक दाल, चावल, आटा, कपड़ा व अन्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाने पर केंद्र सरकार की घोर निंदा की।

भाकपा जिला सचिव पवन शर्मा ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन एवं विश्व आदिवासी दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए केंद्र व राज्य सरकार को नक्सलवाद की

समस्या का समाधान करने में विफल बताया। इसके साथ ही उन्होंने नक्सलवाद से भ्रमित आदिवासियों को मुख्यधारा में जोड़ने हेतु उन्हें जल, जंगल, जमीन का मालिकाना हक देने की मांग की किसान नेता नन्द कश्यप ने सभा को संबोधित करते हुये किसानों और मजदूरों को एकजुट होकर केंद्र सरकार को कारपोरेट घरानों की कठपुतली एवं छद्म राष्ट्रवादी सरकार करार दिया। साथ ही अग्निवीर योजना को वापस लेने की मांग की।

भाकपा के मीडिया प्रभारी व नौजवान सभा के नेता संत निराला ने बढ़ती महंगाई, गिरता रुपया, बढ़ता डॉलर को लेकर केंद्र सरकार पर तंज कसते हुये देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर की साथ ही कारपोरेट घरानों की टैक्स माफी पर सवाल दागे।

किसान मजदूर नेता श्याम मूरत कौशिक ने केंद्र व राज्य सरकार की जनविरोधी नीतियों की जमकर आलोचना कर देश में फैले जातिवाद, सम्प्रदायवाद, गैरबराबरी, धार्मिक उन्माद बढ़ने पर केंद्र सरकार की फासीवादी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।

आमसभा को संबोधित करते हुये एआईएसएफ के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरज शर्मा ने बढ़ती महंगाई, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का जिक्र करते हुये केंद्र

सरकार की जनविरोधी-छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का आह्वान किया।

आप यूथ विंग के नेता सूर्यकांत ने देश के वर्तमान हालातों एवं बस्तर में आदिवासियों की स्थिति पर चिंता व्यक्त कर केंद्र व राज्य सरकारों को समन्वय स्थापित कर सभी को निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को तरजीह दिये जाने की मांग की।

एडवोकेट लखन सिंह ने अपने संबोधन की शुरुआत में हिटलर और मुर्गा कहानी का पाठ कर, जनता को विचारशून्य किये जाने की रणनीति का पर्दाफाश करते हुये देश में बढ़ती अमीरी और बढ़ती भुखमरी का जिक्र करते हुये देश में किसानों-मजदूरों के नेतृत्व में समाजवादी सरकार की स्थापना हेतु संघर्ष करने की अपील की।

पॉपुलर ने आमसभा का संचालन किया।

धरना व आमसभा स्थल पर ही दोपहर 3.30 बजे नायब तहसीलदार श्वेता यादव को धरना-प्रदर्शन से संबंधित राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया।

धरना प्रदर्शन व आमसभा में मुख्य रूप से भाकपा जिला सचिव पवन शर्मा, एच. डी. पाइक, उदयराम टंडन, भरतलाल धुरी, विक्रान्त शर्मा, पुनाराम धुरी, दीपक महंत, गोकुल चौहान,

दुखीराम गेंदले, संत निराला, पावेल शर्मा, दिलीप धुरी, साधूराम धुरी, चिल्लू सिंह, दीपक मसीह, असीम तिवारी,

जगदीश छूरा, तेजसिंह चौहान, रामेश्वर कुर्रे, रमेश बैगा, धीरज शर्मा पेसी यादव आर्युष शुक्ल आदि मौजूद थे।

### खागा फतेहपुर का जिला सम्मेलन संपन्न

खागा फतेहपुर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सम्मेलन शिवगंगा मैरिज हाल खागा में संपन्न हुआ। सम्मेलन में पूरे जनपद से चुने हुए प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यकारिणी के नसीम अंसारी उपस्थित रहे। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए अंसारी ने पूरी दुनिया के राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा की उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश में चल रही सरकारें महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा से जनता का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान का भेद खड़ा करके सांप्रदायिकता फैला कर धुवीकरण की राजनीति कर रही हैं। देश की सार्वजनिक संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों के हाथों औने पौने दामों में बेच रहे हैं, श्रम कानूनों में बदलाव करके कामगारों से 12 से 14 घंटे काम कराने का कानून बना रहे हैं, यह सरकार पूरी तरह से किसान मजदूर व अन्य वंचित तबकों की विरोधी सरकार है। सम्मेलन में जिला मंत्री द्वारा राजनीतिक व संगठन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें 8 लोगों ने अपने सुझाव समर्थन देते हुए अपनी बात रखी। सम्मेलन के अंत में 21 सदस्य जिला काउंसिल का चुनाव किया गया व पांच सदस्यों को आमंत्रित सूची में रखा गया। फूलचंद पाल को पुनः सर्वसम्मति से जिला सचिव चुना गया, रामप्रकाश व राकेश प्रजापति को सह सचिव चुना गया, रामकृष्ण हेगड़े को पार्टी के कोषाध्यक्ष पद पर चुना गया। पार्टी सम्मेलन की अध्यक्षता राम सजीवन सिंह, राधे रमण पांडे, रामचंद्र के 3 सदस्यीय अध्यक्षमंडल ने की तथा संचालन रामप्रकाश ने किया। सम्मेलन का शुभारंभ राम अवतार सिंह द्वारा पार्टी का झंडा फहरा कर किया गया। सम्मेलन के अंत में मोतीलाल एडवोकेट ने सभी आए हुए प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जिले में प्रस्तावित पार्टी राज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी साथी जी जान से जुट जाएं।

## समाजवाद ही भविष्य है और भविष्य....

पेज 4 से जारी...

क्रांतिकारियों के वकील भी थे। यह बताना अनुचित नहीं होगा कि जब अरुणा आसफ अली 1942 में तिरंगा फहरा कर आजादी की लड़ाई का उद्घोष कर रही थी ठीक उन्ही दिनों मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा बंगाल में अंग्रेजों की सरपरस्ती में प्रांतीय सरकार चला रहे थे और क्रांतिकारियों का दमन कर रहे थे।

1947 में आजादी को जिन घटनाओं ने सहज बनाया उनमें सबसे महत्वपूर्ण है-1946 में हुआ नौसैनिक विद्रोह। कौन नहीं जानता कि जब अंग्रेजी नौसेना ने विद्रोह किया तो उन्होंने जो झण्डा हाथ में लिया, उसमें सबसे ऊपर कम्युनिस्टों का प्रतीक लाल रंग ही था।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर जो राजनीतिक पार्टी बनाई वह फारवर्ड ब्लॉक थी। यह पार्टी आज भी वामपंथी मोर्चे का अभिन्न हिस्सा है। आजाद हिंद फौज की कैप्टन लक्ष्मी सहगल आजीवन कम्युनिस्ट रही और कम्युनिस्ट पार्टियों

ने उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भी बनाया था। उनकी बेटी सुहासिनी अली सी.पी.एम. की सांसद रही हैं।

आजादी की लड़ाई में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने का रिकॉर्ड एक कम्युनिस्ट-नक्षत्र मालाकार ने बनाया था। इतना ही नहीं आजादी के बाद हुए पहले आम चुनावों में देश में सर्वाधिक मतों से जीतने वाले उम्मीदवार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रवि नारायण रेड्डी थे।

जाहिर है कि ये कुछ उदाहरण ही हैं और आजादी का इतिहास कम्युनिस्टों के समर्पण और कुर्बानियों से भरा हुआ है। आजादी के तुरन्त बाद सत्ता का हिस्सा बनने की बजाय कम्युनिस्टों ने वंचित लोगों को हक में संघर्ष का रास्ता अपनाया और त्रावणकोर, हैदराबाद और भोपाल जैसी रियासतों के भारत में विलय हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेभागा और तेलंगाना जैसे गौरवशाली आंदोलनों हिस्सा बनीं। बाद के वर्षों में बैंकों, बीमा और खदानों के राष्ट्रीयकरण, देश में एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना और

संवैधानिक मूल्यों के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

आज जब हम आजादी की पचहत्तरवीं सालगिरह मना रहे हैं तब हम कम्युनिस्ट आंदोलन के स्वर्णिम इतिहास को गौरव से याद करते हैं लेकिन वर्तमान चुनौतियों पर नजर डालते हैं तो प्रतीत होता है कि देश को हमारी निस्वार्थ सेवाओं और कुर्बानियों की अभी बहुत जरूरत है। आज हमारा देश और लोकतंत्र जिस तरह के संकटों का सामना कर रहा है वे अभूतपूर्व हैं। आरएसएस-कारपोरेट गठजोड़ की भाजपा सरकार की नीतियां दो तरह से देश को तबाह कर रही हैं-

1. सत्ता में आने और बने रहने के लिए भाजपा ने एक समीकरण का विकास किया है और वह है मतदाताओं का धुवीकरण करते हुए बहुसंख्यक वोट हासिल करना। इसके लिये रोज नित नए शिगूफे खुद और मीडिया के माध्यम से छेड़ते हुए समाज को बुरी तरह साम्प्रदायिक और जातीय आधार पर विभाजित कर दिया गया है।

2. सत्ता में आने के बाद से तमाम फैसले कारपोरेट के फायदे में लिए जा रहे हैं और नंगा दरबारी पूंजीवाद कायम कर दिया गया है। सिर्फ दो उद्योगपति अपनी दौलत में लगातार इजाफा कर रहे हैं और बहुमत जनता महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी का शिकार हो रही है। रोज कोई न कोई सरकारी उद्यम औने पौने दामों मित्र पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है।

ऐसी स्थिति में जब देश गहरे संकट में है, समाज विभाजित हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। देश बचाने के लिये हमें निरंतर सक्रिय होना होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपनी इन बुनियादी मांगों के साथ संघर्ष के मैदान में है। आप सबसे आग्रह है कि साथ में आइये और अपनी आजादी को कायम रखने और मजबूत करने की मुहिम में भागीदारी बनें।

हमारी बुनियादी मांगें इस प्रकार हैं-

1. हर स्तर पर शिक्षा सबके लिये एक समान, निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध हो।

2. सबके लिये सम्मानजनक और स्थायी रोजगार का इंतजाम सरकार कराए। कम से कम वेतन 25 हजार रुपये प्रतिमाह हो और वेतन में 5 गुने से अधिक अंतर न हो।

3. सबके लिये निःशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण आवास सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएं।

4. खेती को लाभदायक बनाने के लिये स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए। मौजूदा समर्थन मूल्य को दोगुना किया जाए और सभी फसलों को इसके दायरे में लाने के लिये कानून बनाया जाए।

5. व्यापक भूमि सुधार कानून लागू किया जाए और जमीन जोतने वालों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया जाए। सभी भूमिहीन परिवारों को न्यूनतम 5 एकड़ जमीन प्रदान की जाए।

6. सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया जाए और इनके विनिवेश पर पूर्ण रोक लगाई जाए।

7. मौजूदा चुनाव प्रणाली लोकतंत्र के लिये बेहतर नहीं है। इसलिये समानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू की जाए।

# स्वामी सहजानन्द सरस्वती: 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण के पुरोधा

प्रताप नारायण सिंह

धन्य है उत्तरप्रदेश का गाजीपुर जिले का देवाग्राम जहाँ बेनी राय शर्मा की चतुर्थ सन्तान के रूप में 1889 ई. में महा शिवरात्रि को नौरंग राय का जन्म हुआ। वही नौरंग राय बाद में स्वामी सहजानन्द के रूप में भारतीय क्षितिज पर उभरकर आए। स्कूली शिक्षा के बाद वर्षों तक समग्र भारत का भ्रमण किया। स्वामी अद्वैतानन्द सरस्वती से दण्ड ग्रहण कर "दंडी" उपाधि प्राप्त करने के फलस्वरूप योग साधना में कुछ समय बिताने के बाद मिली असफलता से सीधे सामाजिक एवं राष्ट्रीय कार्यों में लग गए। उस समय भारत में पुनर्जागरण का दौर था। उत्तरप्रदेश के गाजीपुर में बंगाल की तुलना में 50 वर्ष बाद नवजागरण का दौर आया था। आने के साथ ही गांधीवाद, आर्य समाज एवं साहित्य में द्विवेदी युग की मनो भूमि जुड़ी थी। स्वामी जी समझौतावादी शुरु से ही नहीं थे। वे सत्य को पूरा-पूरा मूल्य देना चाहते थे। सन्यासी जीवन में उनके दो बड़े गुण स्पष्ट दिखते हैं। पहला अकखड़पन और अदम्य साहस। वाल्मीकि ने क्रौंचवध की दुर्घटना पर निषाद यव्याधुद्ध को शाप दिया था। कहा जाता है कि वाल्मीकि की जगह अगर स्वामी जी रहते तो शाप नहीं देते, बल्कि उसे पटककर चढ़ बैठते। क्योंकि स्वामी जी का कवि हृदय नहीं था। वे तर्क और बुद्धि पर अपने प्रभाव को स्थापित करके चलते थे। उनका चिंतन 'वाद' 'प्रतिवाद' के द्वन्द्व से हटकर एक पूर्णता का जीवन तथा सर्वोदय से जुड़ा हुआ था। एक ओर जहाँ गांधीजी वर्ण की बात न करके सर्व की बात करते थे, वहीं दूसरी ओर स्वामी जी वाद-प्रतिवाद के डायलेक्टिक्स के बारे में चिंतन करते थे। उन्होंने भूमिहार आन्दोलन अपने जिला गाजीपुर से प्रारंभ किया था। उस समय किसानों की हालत अच्छी नहीं थी। उस जिले में अधिकांश किसान संयोग से भूमिहार जाति के ही थे। किसान, जमींदारों के जुल्म एवं आतंक से आक्रांत थे। तब उनका ध्यान किसानों की ओर गया। इसी वजह से उनकी अपनी ही जाति के सामन्तों से टकराहट हुई। इससे पूर्व वे स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल हो चुके थे। किसानों के जीवन में वे आमूल-चूल परिवर्तन लाना चाहते थे।

आगे चलकर स्वामी जी ने जाति निरपेक्ष आन्दोलन का श्रीगणेश किया। उस समय किसान सभा में लोग नेता के रूप में आते थे। इसके पीछे मूल कारण यह था कि खेती उस समय विशेषकर सवर्णों के ही हाथों में थी। उन्होंने किसान के साथ किसानी में लगे खेत मजदूर को भी जोड़ना प्रारंभ

कर दिया था। धीरे-धीरे किसान सभा का संगठन बनना प्रारंभ हो गया। परिणाम यह हुआ कि सवर्ण किसान उनसे दूरी बनाने लगे और अवर्ण उनसे जुड़ते गये। परिणाम यह हुआ कि किसान सभा का नेतृत्व पिछड़ी जातियों के हाथ में आ गया। जहाँ तक उपरी नेतृत्व का सवाल था, उसमें हर जाति, हर प्रांत और हर सम्प्रदाय के लोग आ गए थे। इस तरह से उन्होंने एक विस्तृत और अखिल भारतीय मंच का निर्माण कर लिया था। स्वामी जी किसान सभा के संस्थापक के रूप में उभर चुके थे। एक अमेरिकी शोधकर्ता वाल्टर हौजर ने लिखा है- स्वामी जी सन्यासी थे। स्वामी जी का पगहा सन्यास लेते समय ही टूट गया था। माता-पिता का दिया हुआ नाम "नौरंग राय" ही अब लोगों के समक्ष स्वामी सहजानन्द सरस्वती के रूप में आ गया था। इसी दौर में स्वामी जी की चिन्तनधरा बदलकर सैद्धान्तिक मार्क्सवाद की ओर बढ़ने लगा। इससे उनकी लोकप्रियता और बढ़ने लगी। आज जो कुछ मुंगेर और भागलपुर के दियारे में अथवा गया तथा भोजपुर में घटित हो रहा है, उसके अग्निबीज स्वामी जी ही बिखेर कर गए थे। उनका कर्म निष्फल नहीं हुआ। उस दौर में बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की साख स्वामीजी के किसान आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण बढ़ी थी। विडम्बना यह हुई कि वे अपने पीछे एक प्रभावशाली कैडर नहीं छोड़ गए। परिणाम यह हुआ कि किसान सभा का मंच अन्य लोगों ने भिन्न-भिन्न रूपों में दखल कर लिया। आज तो हर राजनीतिक दल अपने-अपने दल के अंदर एक किसान सभा संगठित कर क्यारियों में बांटकर संचालित कर रहा है।

विडम्बना है कि बिहार एवं पूर्वी उत्तरप्रदेश के कुछ युवकों ने "सहजानन्द से चारु मजूमदार तक" नारा दिया है। उन लोगों की समझ है कि चारु मजूमदार के प्रस्थान बिन्दु है सहजानन्द। वास्तविकता यह है कि नक्सली आन्दोलन किसान आन्दोलन है ही नहीं। वह तो भूमिहीन बनाम भूमिवाले की लड़ाई है। चारु मजूमदार का नारा था-बोएगा भूमिवाला, काटेगा भूमिहीन। यहाँ याद रखने की जरूरत है कि स्वामी जी का नारा था बोनेवाला ही काटेगा, इसके लिए चाहे जो भी हो। किसान स्वयं में एक अस्पष्ट शब्द है। चौधरी चरण सिंह के और चारु मजूमदार के अर्थ में भिन्नता है। किसान मूल रूप से सामाजिक एवं सांस्कृतिक शब्द है। व्यास, वाल्मीकि का किसान, लॉर्ड कार्नवालिस का किसान, गांधी जी का किसान, असम, बंगाल में विदेशी हटाओ आन्दोलन और 'धरती पुत्र'

आन्दोलन के संदर्भों का किसान एवं चारु मजूमदार और जंगल सन्थाल का किसान-ये सारे के सारे किसान एक तो है ही नहीं। यह इतिहास की विडम्बना होगी कि किसान शब्द की जो अर्थयात्रा स्वामी जी से शुरु होती है, उसे व्यर्थ तक ले जाकर अघोषित जाति में पहुंचाने की एक साजिश ही रही है। स्वामी जी की समझ थी कि सभी किसानों को जमींदार के खिलाफ एक सूत्र में बंधने की जरूरत है। उनकी समझ थी कि किसान वह जिसकी अपनी खेती हो यानी खेतिहर गृहस्थ। गृहस्थ शब्द का प्रयोग उन्होंने भोजपुरी में गिरहत नाम से किया था। उनकी समझ थी कि खेती लायक जमीन का क्षेत्रफल बढ़ने वाला नहीं है। भूमिहीनों की संख्या तो लगातार बढ़ने वाली है। वे मानते थे



कि भूमिवाले को भूमिहीनों को जमीन देनी पड़ेगी।

आज स्थिति यह है कि कसम खाने के लिए किसान का नाम सभी लेते हैं, लेकिन किसान को केन्द्र में रखकर अधिकांश राजनीतिक दल आर्थिक चिंतन एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता के प्रति संकल्पित नहीं दिखते हैं। अभी पूरे देश में कपटाचार चल रहा है। इन दिनों जो कुछ भी विकास या ऋद्धि-सिद्धि हासिल की जा रही है, वह केवल शहरी उपभोक्ता यानी बिचौलिया व्यापारी वर्ग एवं नौकरी पेशा वर्ग, इन्हीं दोनों के लिए है। ऐसी नीति बन चुकी है जिससे अनाज का भाव न बढ़ने पाये, लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य को अपने भाव (मूल्य) आसमान तक बढ़ाने की छूट है। अभी डीजल एवं पेट्रोल का मूल्य लगातार बढ़कर सौ पार कर चुका है। दवाई के दाम में बेशुमार वृद्धि हो चुकी है। वर्तमान समय में प्रशासन, व्यापारी एवं नौकरी पेशा में नियुक्त शहरी उपभोक्ता, इन तीनों का एक त्रिकोण बन चुका है। विधायक एवं सांसदों के वेतन भत्ते में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ये त्रिकोण किसानों के प्रतिकूल कपटाचार कर रहा है। ऐसी स्थिति में किसान की असल लड़ाई इस खर-दूषण त्रिशिरा पोषक सरकार से है।

किसान बनाम जमींदार के बीच की लड़ाई अब अप्रासंगिक हो चुकी है। आज समस्या खेतिहर बनाम खेत मजदूर के बीच है। भूमिहीन बनाम भूमिहीन के बीच भी मतभेद बढ़ता जा रहा है। स्वामी सहजानन्द गृहस्थ के साथ उनके निजी मजदूर को देखते थे। दोनों को मिलाकर एक इकाई मानते थे। आज भी अखिल भारतीय किसान सभा उनके बताए मार्ग पर चल रहा है। भारतीय किसान की विडम्बना यह है कि औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों एवं जमींदारों के द्वारा दमन एवं शोषण का शिकार होकर कराहते रहे। आजादी के बाद भी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण भारतीय किसान घाटे की खेती करने के लिए विवश है। आजादी के बाद आज तक लाखों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। स्वामी जी के जमींदारों के खिलाफ संघर्ष से प्रभावित होकर जब बिहार में पहली बार 1967 में गैर कांग्रेसी संविद की सरकार बनी थी तो उस सरकार में शामिल भाकपा के कामरेड इन्द्रदीप सिन्हा ने राजस्व मंत्री के रूप में सबसे पहले टाटा की जमींदारी समाप्त करने की घोषणा कर उसे कानूनी जामा पहनाया था। इसी तरह जब 1996 में केन्द्र सरकार बनी थी। तो कामरेड चतुरानन मिश्र केबिनेट कृषिमंत्री बने थे। उन्होंने सर्वप्रथम किसानों को फसल बीमा योजना के माध्यम से बाढ़, सुखाड आदि प्राकृतिक प्रकोप से राहत के लिए फसल बीमा कानून बनवाने में सफल हुए थे। 1996 के पूर्व अधिकांश कृषि क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य बड़े-बड़े शहरों में होते रहे थे। संयोग से बिहार के बेगूसराय जिले ने 1996 में ही भाकपा के दो सांसदों रमेन्द्र कुमार एवं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह को दिल्ली के पार्लियामेंट में भेजने में सफल हुए थे। दोनों सांसदों ने कृषि मंत्री से मिलकर बेगूसराय जिले के सदर प्रखंड अन्तर्गत कुसमहौत में मक्का अनुसंधान केन्द्र की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करवायी थी। ये स्वामी सहजानन्द के सपनों को साकार करने का ही एक सफल प्रयास था। वर्तमान में अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव अतुल कुमार अनजान स्वामीनाथन आयोग के सदस्य के रूप में रहकर उनके निर्देशन में पूरा रिपोर्ट तैयार की थी। विगत वर्ष देश भर के किसान तीन कृषि काले कानूनों के खिलाफ 378 दिनों तक आन्दोलन चला। इस आन्दोलन में किसानों ने भीषण गर्मी, मूसलाधर वर्षा, कपकपाती टंडक में भी दिल्ली के बोर्डरों पर अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत रहे। आन्दोलन के क्रम में 700 से अधिक किसान काल कवलित हो गए। यह आन्दोलन पूरे विश्व के लिए

ऐतिहासिक था। आज भी अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानन्द के द्वारा स्थापित मूल्यों को पाथेय मानकर पूरे देश में संघर्ष की मशाल जला रहे हैं। बिहार राज्य किसान सभा आज भी गौरवान्वित है कि स्वामी सहजानन्द की कर्मभूमि बिहार रही है। बिहार राज्य किसान सभा गौरवान्वित है कि 26 जून 2012 को सहजानन्द की कर्मभूमि पटना के बिहटा में चार दिवसीय राष्ट्रीय स्तर पर हीरक जयन्ती का आयोजन कर लिए गए संकल्प के अनुसार किसानों की समस्याओं के निदान के लिए अनवरत आन्दोलन चल रहा है। संयुक्त किसान आन्दोलन में भी बिहार राज्य किसान सभा के सदस्यों ने दिल्ली बॉर्डर पर अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति दी थी, साथ ही राज्य के अन्दर भी संयुक्त किसान आन्दोलन के आह्वान पर भारत बंद में भी बढ़-चढ़कर किसानों ने भागीदारी दी थी।

भारत की किसानी भारत की अस्मिता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की किसानी को खत्म करने की भरपूर कोशिश की थी, मगर उनका सपना पूरा नहीं हुआ। आज आजादी के 75वें वर्ष में भारत की किसानी का कारपोरेटीकरण करने की साजिश की जा रही है। भारत के लोग अन्य कुछ को सहन कर सकते हैं, लेकिन वे किसानी नहीं छोड़ सकते हैं। प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता है। भारत के लोगों की रगों में किसानी हजारों वर्षों से चली आ रही है। स्वामी जी के किसान आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव के कारण ही 1960 के दशक में बिहार के अन्दर सवर्णों का मध्यम वर्ग का एक हिस्सा कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए थे। उन्हें लगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ही किसानों की समस्या का हल ढूँढ़ सकता है।

इस प्रकार से सहजानन्द ने न केवल किसान आन्दोलन को आगे बढ़ाया, बल्कि कम्युनिस्ट आन्दोलन को भी गति प्रदान की। 1930 में नमक कानून भंग करने की वजह से स्वामी जी को छः माह के कारावास की सजा हजारीबाग जेल में रहकर बिताना पड़ी थी। उन्होंने मार्क्सवाद को गीता धर्म का आधुनिक रूप दिया। 1934 में बिहार में आये भूकम्प में पीड़ितों की सेवा की। 1935 में पटना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना एवं राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ के गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल हुआ। इसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानन्द सरस्वती ने की थी। इस सम्मेलन में पंडित जवाहर लाल नेहरू, पुरुषोत्तम शेष पेज 15 पर...

भाजपा लोगों की समस्याओं को हल करने में बुरी तरह विफल रही है। भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी का खतरा उनके 8 साल के शासन के बाद से लगातार बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में भाजपा उपरोक्त समस्याओं से लोगों का ध्यान भटका रही है और लोगों में सांप्रदायिक जहर घोल रही है। संयुक्त आंध्र प्रदेश की विधानसभा में भाजपा के पूर्व विधानसभा दल के नेता पी नागेश्वर राव ने खम्मम भाजपा जिला सम्मेलन में बालते हुए ये बातें कहीं। वे शुक्रवार को 22वें खम्मम जिला सम्मेलन के अवसर पर ब्यारा रिंग रोड सेंटर में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व परचुरी उद्यान से एक प्रभावशाली रंगारंग विशाल जुलूस निकाला गया।

## भाजपा का खम्मम जिला सम्मेलन संपन्न



सम्मेलन के लिए आयोजित जनसभा की अध्यक्षता पार्टी के जिला सचिव पोटू प्रसाद ने की।

पी नागेश्वर राव ने आगे संबोधित करते हुए कहा है कि एक तरफ देश में भूख, गरीबी बढ़ रही है, मोदी सरकार उन लोगों की आवाज दबा रही है जो सरकार की चूक और कृत्यों पर सवाल उठा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों के लिए सांप्रदायिक ताकतों को हराने के लिए एकजुट होने का समय आ गया है। भाजपा की नीतियों से देश में लोकतंत्र खतरे में है। यह प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो आदि का उपयोग करके विभिन्न दलों के नेताओं की आवाज को दबाने और उन्हें अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है। भाजपा ने विभिन्न राजनीतिक दलों के अन्य नेताओं को अपने खेमे में लाने के लिए एक समिति नियुक्त की है। इस कदम से स्थिति की भयावहता को आसानी से समझा जा सकता है। इस महत्वपूर्ण स्थिति में भाजपा के कारवां को रोकने के लिए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों को एकजुट होना चाहिए।

भाजपा तेलंगाना के राज्य सह सचिव के संबाशिव राव, ने संबोधित करते हुए कहा है कि मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में एक तानाशाह की तरह

व्यवहार कर रहे हैं, जबकि केसीआर अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। भाजपा उन लोगों को लक्षित कर रही है जो सरकार पर सवाल उठाते हैं। यही कारण है कि भाजपा मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक वृद्ध व्यक्ति वरवर राव और एक विकलांग प्रोफेसर को साईबाबा को सलाखों के पीछे भेज दिया है। वर्तमान सत्ताधारी दल शोषण की पार्टियों के रूप में बने रहे। क्या इन पार्टियों ने कोई बलिदान किया है? संबाशिव राव ने पूछा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन मोदी आरएसएस और वल्लभ भाई पटेल दोनों की तारीफ कर रहे हैं। इस संबंध में मोदी को इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। 1200 जिंदगियों के बलिदान से तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। लेकिन क्या तेलंगाना राज्य सरकार ने पेंशन, राशन कार्ड, डबल बेड रूम हाउस, प्रत्येक दलित को 3 एकड़ जमीन, बेरोजगारी राहत और रोजगार सृजन आदि प्रदान किया? कुनमनेनी ने तकलीफ से पूछा। केसीआर परिवार को तो लाभ हुआ है लेकिन राज्य के लोगों को बिल्कुल भी लाभ नहीं हुआ है। टीआरएस पार्टी गुटों में बंट गई है। कांग्रेस पार्टी ने धोखा दिया है। इस तरह के धोखे से यह टूट जाएगी। हम देख सकते थे कि जिले के छह निर्वाचन क्षेत्रों में कांग्रेस का चुनाव हुआ, लेकिन कांग्रेस ने रामुलु मेल को वोट दिया। वर्तमान में यह रामुलुनाइक कहां है? अंत में उन्होंने कहा है कि सम्मेलन लोगों के मुद्दों से संबंधित भविष्य के संघर्षों के कार्यक्रमों को तय करेगा। सम्मेलन को भाजपा राज्य सचिवमंडल सदस्य बी हेमंत राव, राज्य कार्यकारिणी सदस्य सबर पाशा, आर राम प्रसाद, दांडी सुरेश आदि ने संबोधित किया।

प्रतिनिधिमंडल सत्र को प्रजापक्ष के संपादक भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य के श्रीनिवास रेड्डी ने संबोधित किया। उन्होंने लेटिन अमेरिका में वाम दलों की चुनावी जीत के बारे में विस्तार से बताया।

## स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य: आजादी की वर्षगांठ पर समर्पित एक संगोष्ठी

सीवान: प्रगतिशील लेखक संघ एवं पीपुल्स कल्चरल स्कॉड सीवान के संयुक्त तत्वावधान में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित एक संगोष्ठी—“स्वतंत्रता आंदोलन और साहित्य” विषय पर 7 अगस्त 2022 को डाक बंगला रोड सीवान पर कौमी एकता के वाहक वरिष्ठ उस्ताद शायर कमर सीवानी, डॉ. श्रीमती सुशीला पाण्डेय, वीरेन्द्र कुमार, गोपालजी श्रीवास्तव की अध्यक्षमंडली में धूमधाम से संपन्न हुई। कार्यक्रम के आरंभ में अतिथियों का माल्यार्पण और कलाकारों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात प्रगतिशील लेखक संघ एवं पीपुल्स कल्चरल स्कॉड सीवान

के अध्यक्ष प्रसिद्ध होमोपैथिक चिकित्सक डॉ. सतीन्द्रनाथ सिन्हा ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम उद्घाटन डॉ. ब्रजनन्दन किशोर ने शहीद स्मृति पर दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद पीपुल्स कल्चरल स्कॉड के कलाकारों ने बड़ा ही मार्मिक शहीद गीत—“सलाम उन शहीदों को जो खो गये, वतन को जगाकर जो खुद सो गये....” इसी क्रम में समूहगान—“दीप जिनका महालात ही में जले, चंद लोगों के खुशियों को लेकर चले....”, “मुसलमां हिन्दू की जान कहा है मेरा हिन्दुस्तान उसे मैं दूँ रहूँ हूँ....”, “हरी-हरी सावन में पड़े लागल बुनिया रोये लल मुनिया ए हरी...” आदि प्रस्तुत किया गया। गीत

के बाद अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. ब्रजनन्दन किशोर ने कहा कि भारतेन्दु युग से लेकर आज तक स्वाधीनता आंदोलन कहीं न कहीं भारतीय राजनीति और जन संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। स्वाधीनता का बोध किसी भी साहित्य का प्राण होता है। साहित्य इसके बिना अल्पायु होगा। डॉ. जीतेन्द्र वर्मा ने आलेख पाठ के क्रम में कहा कि सर्वविदित है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आजादी की जो भावना मचल रही थी वह भावना प्रेमचंद तक आते-आते हिन्दी में मुखर हुई। आलेख पर बोलते हुए वरिष्ठ उस्ताद शायर अध्यक्षमंडल के सदस्य कमर सीवानी ने यूँ कहा—“सर जमीं ने

हिन्दी की शानों फजीलत को सलाम, जौंने साराने वतन के जोशे हिम्मत को सलाम, जिन शहीदों की शहादत से आजादी मिली उन शहीदों की वफादारी की अजमत को सलाम.....” मंडली के सदस्य डॉ. सुशीला पाण्डेय ने कहा कि अपने नयी पीढ़ी को स्वतंत्रता के लिये कवियों, शायरों, लेखकों की रचनाओं से अवगत कराने की जरूरत है। देश प्रेम का संदेश उन्हें दें, कुकृत्यों से उन्हें बचाये तभी हमारी आजादी बरकरार रहेगी। मंडली के सदस्य वीरेन्द्र कुमार ने कहा कि आज पूरे देश में अनुष्ठानिक आजादी का घोषित अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है जिनका आजादी से कोई सरोकार नहीं रहा।

अन्य वक्ताओं में प्रमुख थे—गोपालजी श्रीवास्तव, म.अनवर साहब, उमाशंकर प्रसाद, वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, पारसनाथ श्रीवास्तव, जागृति के दीपक कुमार, रामकिशुन अकेला, डॉ. आर.एन. पाण्डेय, डॉ. राजेन्द्र सिंह, विजयलक्ष्मी विनोदिनी, डॉ. यतीन्द्र नाथ सिन्हा, डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव, ठाकुर पाण्डेय, डॉ. प्रवीण कुमार सिंह, डॉ. विनय कुमार, कुमारी विभा आदि। समस्य कार्यक्रमों का सफल संचालन—प्रसिद्ध रंगकर्मी प्रलेस एवं पीपुल्स कल्चरल स्कॉड के सचिव डॉ. अनिल कुमार श्रीवास्तव ने किया और धन्यवाद ज्ञापन श्रीमती बच्ची देवी ने किया।

“इंसानी जिन्दगी का दायरा सिर्फ इश्क और मुहब्बत तक महदूद नहीं। क्या इसके अलावा और बहुत से मसाइल और बहुत सी दिलचस्प और गैर दिलचस्प चीजें नहीं हैं, जिनसे हम बावस्ता हैं? इन चीजों को छोड़कर हम खला-ए-महज में रहकर इश्क नहीं कर सकते।” “लंदन की एक रात” उपन्यास के आखिर में नायक हीरेन की तरफ से अपनी महबूबा शीला ग्रीन पर जाहिर ये जज्बात केवल हीरेन के ही नहीं, बल्कि खुद सज्जाद जहीर के हैं, जिसकी बिना पर वह ताजिंदगी चले। जब जिन्दगी की यह समझ बनी, तो एक बड़े मकसद के लिए वह हिन्दुस्तान लौट आए। न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई के दौरान अंग्रेजों की हिकारत के शिकार रहे, सज्जाद जहीर ने एक मजबूत इरादे के साथ लंदन छोड़ा था, जिसका जिक्र ‘लंदन की एक रात’ के क्लाइमैक्स में भी मिलता है। उपन्यास के हीरो हीरेन का किरदार यदि देखा जाए, तो यह उनकी जाती जिन्दगी से बहुत हद तक मेल खाता है। दरअसल, ‘लंदन की एक रात’ के कई किरदार हकीकतनिगारी के चलते सच्चाई के बेहद करीब लगते हैं। यथार्थ की बेबाक अक्कासी से उपन्यास की जो जमीन तैयार हुई है, वह बेहद पुरअसर है। यह सज्जाद जहीर का पहला और आखिरी उपन्यास था। हालांकि इसकी समग्र प्रभावशीलता इसे हर दौर में नए मायने देगी। और यही प्रासंगिकता इसे क्लासिक का दर्जा देती है।

उपन्यास लिखने के पसमंजर को देखा जाए, तो सज्जाद जहीर ने जब यह उपन्यास लिखा तो लेखन के तजुर्बे के नाम पर उनके पास 1932 में छपे कहानी संग्रह ‘अंगारे’ में शायी हुए कुल जमा तीन अफसाने और एकांकी ‘बीमार’ था। ‘लंदन की एक रात’ लिखने के बारे में सज्जाद जहीर ‘रोशनाई’ में लिखते हैं, “भला चंद कहानियां और एक नाटक लिखना एक बात और लेखक बनना दूसरी बात थी। ‘अंगारे’ की मकबूलियत लंदन के हिन्दुस्तानियों तक पहुंच चुकी थी। मुझे इसकी तो खुशी थी कि अदबी मैदान में मेरी शुरुआती कोशिशों ने पूर्ववर्तियों की दाढ़ियां झुलसा दी थीं। इससे भी बड़ा इत्मिनान था कि अब्दुल हक ने उर्दू में इन अफसानों को अच्छा कहा था। लेकिन अपनी साहित्यिक योग्यता के बारे में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं था। इस साहित्यिक हलचल में अपनी आत्मा की निष्ठा को बचाने के लिए मैंने ‘लंदन की एक रात’ शुरू किया।” बहरहाल, अपने दिल की आवाज और मुआशरे के प्रति उनकी बेलाग निष्ठा ने ‘लंदन की एक रात’ को जन्म दिया। एक लिहाज से देखें, तो ‘लंदन की एक रात’ में सज्जाद

## पुनःपाठ: लंदन की एक रात (उपन्यास)

# लंदन की एक रात, हिंदोस्ता का नया सबेरा

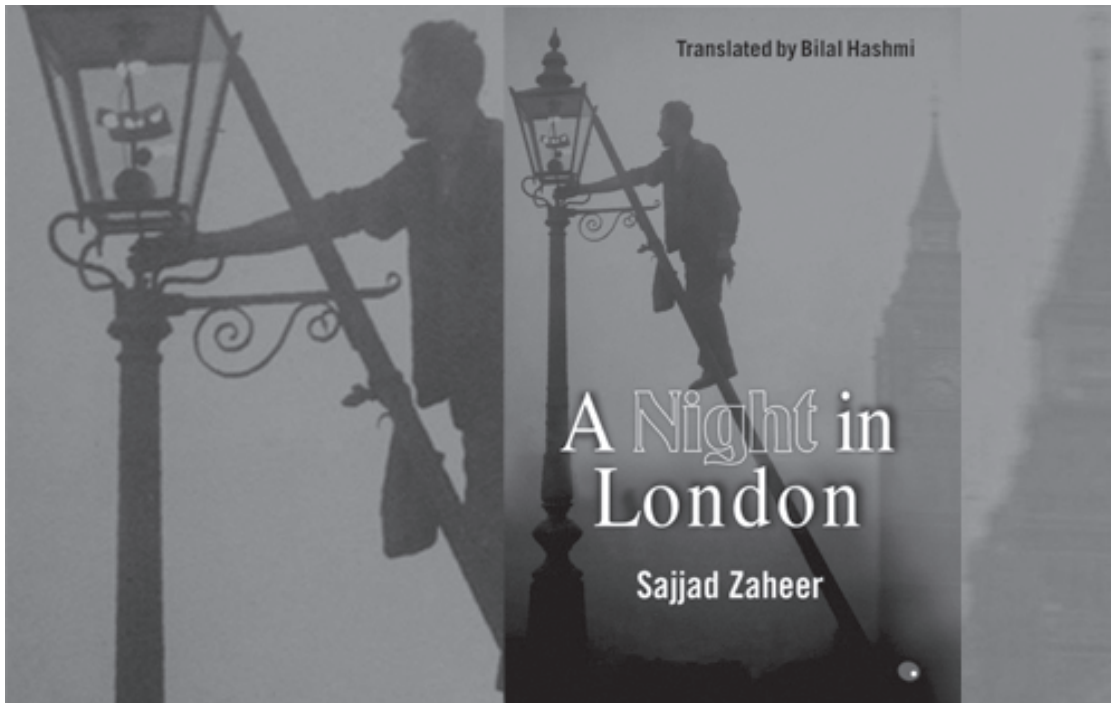
जाहिर खान

जहीर ने अपनी आने वाली जिन्दगी का एक ऐसा ब्लू प्रिन्ट तैयार किया था, जिसे उन्होंने बाद में सरअंजाम दिया।

अपने उपन्यास में लंदन में रह रहे हिन्दुस्तानी तालिबे-इल्म के मार्फत सज्जाद जहीर ने जज्बात का जो इजहार किया है, वह उनकी सोच का पता देता है। उपन्यास में ‘राव’, ‘एहसान’, ‘हीरेन’ की शकल में वह बार-बार पाठकों से मुखातिब होते हैं। किरदारों की तमाम दलीलें हमें सोचने को मजबूर करती हैं। राव और आजम के बीच बातचीत के दौरान राव जिस तरह से हिन्दुस्तान की लीडरशिप पर तंज करता है, वह काबिले-गौर तो है

साया मुल्क पर फैलता जा रहा है, दूसरी तरह जुल्मों जन्न का जाल चारों तरफ से हमको जकड़ता जा रहा है। क्या अच्छे हमारे भलाई करने वाले हैं।” यह संवाद गवाह है कि सज्जाद जहीर हिन्दुस्तान में चल रही उस समय की सियासी हलचल से अच्छी तरह से वाकिफ थे और वाबस्ता भी। मुल्क की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ विचारधारा वाले सियासतदानों ने जो रास्ते इख्तियार किए थे, वे किसी से भी पूरी तरह से मुतमईन नहीं थे। वहीं हिन्दुस्तान की आजादी के लिए अपनाए

बात आसानी से आ जाती है कि उसकी मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए, मगर अभी आदमी की समझ में इस बात का आना बहुत मुश्किल है। इस वजह से नहीं कि ये कोई बड़ी पेचीदा बात है, बल्कि इस वजह से कि इसमें उसका नुकसान है। लेकिन इस गिरोह के वो इक्के-दुक्के लोग जो मेहनत और मजदूरी करने वालों के इंकलाबी नजरिये को कुबूल करके उस पर अमल करने के लिए भी आमादा होते हैं, ज्यादातर तालिब-ए-इल्म के ही तबके में से निकलते हैं। क्या ये बहुत बड़ी गलती न होगी, अगर हम इस बात की कोशिश भी न करें कि हम उन तालिब-ए-इल्मों को जो हमारे नए



ही मआनीखेज भी है।” वतन की भलाई के लिए कोशां हैं! जरा मुझे बताइये तो सही, कौन? किसी को यह तक तो मालूम नहीं कि वतन की भलाई है किस चिड़िया का नाम। उसके लिए कोशां होना, तो दरकिनार। जनाना बनकर चर्खा कातने में वतन की भलाई है या महात्मा गांधी की तरह सच की खोज करने में वतन की भलाई है? या सोशल रिफॉर्म और अछूत कॉफ्रेंस में हिस्सा लेने में वतन की भलाई है? सरकारी मुलाजमत में वतन की भलाई है? या हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग में काम करने में वतन की भलाई है? हर शख्स के पास वतन की भलाई का एक नुस्खा है। हर शख्स मालूम होता है, वतन की भलाई के लिए कोशां है! हर शख्स पुकार-पुकार कर कहता है कि वतन की भलाई के लिए काम कर रहा है। हद हो गई इनकी देखा-देखी अंग्रेजी गवर्नमेंट तक कहने लगी कि वह भी हिन्दुस्तान की भलाई चाहती है! और मुल्क की हालत क्या है? एक तरफ तो गुरबत और भूख का

जा रहे तौर-तरीकों से भी वे नाखुश थे।

हालात से मजबूर हो समझौता कर लेने की राव की खीझ और अहसान के बागियाना अंदाज के तेवर कई जगह पर एक नई जंग के आगाज को आवाज देते हैं। अहसान और हीरेन सज्जाद जहीर के तसव्वुर के नायक हैं। अहसान के राव और करीमा बेगम के साथ जिरह के तर्क उस दौर के हालात पर जबरदस्त चोट करते हैं। अहसान के जेहन में एक ऐसे निजाम का तसव्वुर है जिसमें मजदूर, दलित, महिलाओं और हाशिए से नीचे के लोगों को भी उनके हक और इंसाफ मिलें। जाहिरा तौर पर उपन्यास में अहसान की बातें इश्तिराकियत (साम्यवाद) की ओर इशारा करती हैं। जो बिला गरज उस वक्त के हालात और मौजूदा दौर में भी बेहद जरूरी जान पड़ती हैं। “ये तब्दीली, ये समझ यकवारगी किसी में पैदा नहीं होती, बल्कि बरसों की दिमागी और जिस्मानी मशक्कत का नतीजा होती है। मजदूर की समझ में तो ये

ख्यालात को कुबूल करने की सलाहियत रखते हैं, वो जिनके दिल मुर्दा नहीं हो चुके हैं और जिनके दिमाग मुअत्तल नहीं हैं और जिनके जिस्म काम करने से नहीं भागते, हम उनको उस रास्ते की तरफ लाने में मदद दें, जिधर जिन्दगी की रोशनी है, जिधर तकलीफ और मुसीबत, मुश्किल तो जरूर है लेकिन मौत का घटाटोप अंधेरा नहीं, जिधर हर बेहूदा बेहिंसी का नाम खुशी नहीं बल्कि जिधर मसरत का एक नया अहसास है, कुदरत की अंधी ताकतों को जेर करने की मसरत, इंसानों को बेशऊरी, बद-नज्मी और खुदगर्जी की बरबरियत से निकालकर एक मुनज्जम, मुहज्जब और मुतमदिन दुनिया बनाने की मसरत, काम की मसरत, मेहनत और मशक्कत की मसरत।” सज्जाद जहीर को मजदूरों, नौजवान तालिब-ए-इल्मों में ही उम्मीद की लौ दिखती है। उनका मानना था कि दुनिया का कोई भी बड़ा बदलाव नौजवानों की हिस्सेदारी के बिना मुमकिन नहीं।

‘लंदन की एक रात’ में मुख्य किरदार हीरेन का दाखिला उपन्यास के आखिर में होता है। आखिरी सफों पर जिस तरह उस किरदार और उसके जज्बात, ख्यालात की अक्कासी सज्जाद जहीर ने की है, वह पाठकों पर पुरजोर असर करती है। हीरेन की मेहबूबा शीला ग्रीन, नईम को जब अपने माजी और जाती जिंदगी में दाखिला देते हुए हीरेन और अपनी कहानी सुनाती है, तब उपन्यास की असल कहानी खुलती चली जाती है। सज्जाद जहीर ने इसके लिए फ्लैश बैक का सहारा लिया है। उपन्यास में यह फ्लैश बैक कहीं भी शिथिलता या बोझिलता नहीं लाता, बल्कि हीरेन के आते ही पाठकों की उपन्यास में जो बेताबी बरकरार थी, वह अपने अंजाम को पहुंच जाती है। पाठक हीरेन पाल और शीला ग्रीन की कहानी से पूरी तरह जुड़ जाते हैं। शैली के नजरिये से देखा जाए, तो यहां सज्जाद जहीर बिल्कुल वर्जीनिया वूल्फ की शैली का अनुसरण करते हैं। स्विटजरलैण्ड की वादियों का कलात्मक ब्योरा, लंदन की रात की लाजवाब अक्कासी, इंसानी जज्बात का उपन्यास में शिद्दत से इजहार और शीला ग्रीन-हीरेन पाल की नाकाम मोहब्बत पाठकों के दिलो-दिमाग पर माकूल असर डालती है।

रसेल स्कवॉयर के अन्डरग्राउण्ड स्टेशन पर आजम द्वारा अपनी प्रेमिका जेन के इंतजार से हुई उपन्यास की इब्तिदा आहिस्ता-आहिस्ता अपनी मंजिल पर पहुंचती जाती है। मंजिले मकसूद है हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तानी अवाम और उसकी आजादी। लंदन में ऊंची तालीम हासिल करने के बाद सिविल सर्विसेज में नौकरी के खाब बुनते हिन्दुस्तानी नौजवानों को अपने वतन से दूर रहकर इस बात का एहसास होता है कि वह हिन्दुस्तान में रहें या इंग्लिस्तान, वे जब तक गुलाम रहेंगे अंग्रेजों की नजर में नेटिब्ज, काले, ब्लैकी ही रहेंगे। गुलामी का यह टीका, मुल्क की आजादी के साथ ही उनकी पेशानी से छूटेगा। उपन्यास में लंदन की वह एक रात फैसले की रात है। सज्जाद जहीर ने जिस अंदाज का शिल्प गढ़ा है, उससे कहीं लगता कि यह उनका पहला ही उपन्यास है।

हिन्दुस्तानी तहजीब, अदब, ललित कलाओं, रूहानियत के नुक्तों पर और अवाम के तमाम मसलों पर वह जिस तरह से अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, बहुत हद तक वही तो खास हैं। इसमें उनके तरक्कीपसंद नजरिये का साफ-दीदार होता है। हीरेन की शीला ग्रीन से हिन्दुस्तानी रूहानियत के बारे में की गई बातें खास तौर पर गौर करने लायक है, “मैं तुमसे उस मुल्क के बारे में क्या कहूँ! हमारे यहां शेष पेज 15 पर...

## राज बहादुर गौड़: असाधारण...

पेज 5 से जारी...

टुकड़ियों से मुलाकात हो गई जब वे झरनों का पानी पीने लगे थे। फलस्वरूप उन्हें पीछे झाड़ियों में लौटना पड़ा। इस कोशिश में राजबहादुर अपना 'मार्क फोर' राइफल खो बैठे। राजबहादुर और दो अन्य का पीछा सैनिकों ने किया और वे पकड़े गए। कृष्णमूर्ति झाड़ियों के पीछे से यह सारा नजारा देख रहे थे। राजबहादुर के 2 साथी पायला रामचंद्र रेड्डी और सीतारामी रेडी को पकड़ लिया गया और मिलिट्री कैम्प में गोली मार दी। राजबहादुर की जान इसलिए बची कि वे तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष और निजाम विरोधी संघर्ष के जाने-माने नेता थे। उन्हें उन्हें बचाने के लिए एस राधाकृष्णन तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं ने हस्तक्षेप किया। फल स्वरूप वे बच गए।

राजबहादुर को राईफलों से पीटा गया और वारंगल ले जाकर बेड़ी डंडियों में बांध दिया गया। उन्हें 3 दिनों तक लगातार यातनाएं दी गईं। बाद में उन्हें हैदराबाद जेल स्थानांतरित कर दिया गया जहां उनकी मुलाकात मखदूम और कई अन्य साथियों से हुई। इस बीच पार्टी ने हथियारबंद संघर्ष वापस लेने और आम चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला ले लिया।

### विवाह

बृजरानी और राजबहादुर 1943 से ही एक दूसरे से परिचित थे। इस समय बृजरानी पार्टी में शामिल हो चुकी थी और महिलाओं के बीच काम करती थी। इसके अलावा उसने कांग्रेस सत्याग्रह में भी हिस्सा लिया। वह कई बार जेल गई और अंडर ग्राउंड रही। ब्रज रानी और राज बहादुर 1948 में विवाह के बंधन में बंध गए जब वे अंडरग्राउंड ही थे। इससे पहले राजबहादुर का विवाह 1939 में संयोगिता के साथ हुआ था जो आजमगढ़ की थी। लेकिन सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों के कारण यह दोनों साथ नहीं चल पाए और एक दूसरे से अलग हो गए और तलाक ले लिया।

### आम चुनाव और उसके बाद

कम्युनिस्ट पार्टी ने 1951 में हथियारबंद संघर्ष वापस ले लिया और सारे देश में होने वाले प्रथम आम चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला लिया। बीटीआर के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव का बायकाट करने का फैसला लिया था। राजबहादुर गौड़ ने जेल से ही मुशीराबाद सीट से चुनाव लड़ने का नामांकन दाखिल किया। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण चुनाव नहीं लड़ पाए। बाद में मई 1952 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। उन्हें 13 मई 1952 को रिहा किया गया ताकि पहले ही दिन राज्यसभा के अधिवेशन में भाग ले सकें भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष एस. राधाकृष्णन ने जोर दिया कि सदन का कोई भी सदस्य जेल में ना रहे। राजबहादुर 1956 में फिर से चुने गए लेकिन उन्होंने तीसरी बार चुने जाने से इंकार कर दिया क्योंकि वे शहर पार्टी सचिव थे।

### पार्टी में स्थान

राजबहादुर हैदराबाद शहर समिति के 1940 के दशक में सचिव रहे और 62 में भी। वे क्षेत्रीय पार्टी के तथा बाद में राज्य पार्टी कार्यकारिणी के सदस्य रहे, वे आगे चलकर 1969 से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य चुने गए चुने गए, 1975 से 1988 तक पार्टी की केन्द्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। वे केंद्र से प्रकाशित पार्टी के उर्दू अखबार कम्युनिस्ट जायजा के संपादक रहे और 1978 से ट्रेड यूनियन डिपार्टमेंट के इंचार्ज।

70 वर्ष की उम्र पहुंचने पर उन्होंने एक एक कर संगठन के पदों को छोड़ना शुरू किया। वे कई पार्टी और ट्रेड यूनियन संगठनों के पदाधिकारी रहे। 1954 में एआईटीयूसी के कोषाध्यक्ष चुने गए और 1986 में इसके उपाध्यक्ष।

उसके अलावा प्रगतिशील लेखक संघ और अन्य संगठनों ने काफी सक्रिय रहे। वे स्वयं एक जाने-माने लेखक थे और लेखकों एवं कलाकारों के बीच उनका व्यापक संपर्क था। उन्होंने बड़ी संख्या में पुस्तकें और लेख लिखे।

राजबहादुर दौड़ की मृत्यु 7 अक्टूबर 2011 को 93 वर्ष की आयु में हो गई। उनका शरीर रिसर्च के काम के लिए ओसमानिया मेडिकल कालेज को दान में दे दिया गया।

राजबहादुर को 'युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड' से आजादी के आंदोलन और सामाजिक कार्य के लिए नवाजा गया।

## पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1. मध्यकाल में औरतों की बलियां और हत्याएं	केशव चंद्र	120.00
2. आरक्षण किसके लिए?	पी.एस. कृष्णन	30.00
3. लाल झंडे का इतिहास	अनिल राजिमवाले	50.00
4. साम्प्रदायिक इतिहास और राम की अयोध्या	रामशरण शर्मा	15.00
5. भारत में राज्य की उत्पत्ति	रामशरण शर्मा	50.00
6. मुक्तिबोध की संकलित प्रगतिवादी रचनाएं	राजेन्द्र राजन	200.00
7. राहुल निबंधावली-साहित्य	राहुल सांकृत्यायन	90.00
8. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
9. हम अच्छे कम्युनिस्ट कैसे बनें	ल्यू शाओ ची	50.00
10. विवाद ग्रस्त मस्जिद-एक ऐतिहासिक छानबीन	सुशील श्रीवास्तव	75.00
11. मजूरी, दाम और मुनाफा	कार्ल मार्क्स	25.00
12. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
13. जन-जातियों के धार्मिक विश्वास	...	330.00
14. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
15. विवेकानंद सामाजिक राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
16. हिंदू राष्ट्रवाद और उसका यथार्थ	कृष्णा झा	65.00
17. राजनैतिक अर्थशास्त्र और विश्व आर्थिक संकट	अनिल राजिमवाले	65.00
18. मार्क्सवादी डाइलेक्टिक्स की मूल समस्याएं	अनिल राजिमवाले	75.00
19. पाप और विज्ञान	डाइसन कार्टन	50.00
20. मैं नास्तिक क्यों हूँ	विपिन चन्द्र	30.00
21. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
22. शिवाजी कौन थे?	गोविन्द पानसरे	60.00
23. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
24. कार्ल मार्क्स-भारत संबंधी लेख	कार्ल मार्क्स	80.00
25. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00
26. भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम-1857-59	कार्ल मार्क्स	125.00
27. प्राचीन भारत में जनजीवन	एस.आर. भट	200.00
28. भारत आदिम साम्यवाद से दास प्रथा तक का इतिहास	श्रीपाद अमृत डांगे	30.00
29. मनुष्य और समाज	.....	200.00
30. भारतीय विवाह संस्था का इतिहास	विश्वनाथ काशीनाथ राजवडे	170.00
31. बाल हृदय की गहराइयां	वसीली सुखोम्लीन्स्की	85.00
32. मां	माक्सिम गोर्की	125.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	200.00
34. राज्य और क्रान्ति	लेनिन	60.00
35. साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	70.00
36. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स, एंगेल्स	50.00
37. रूपवती वासिलीसा-अद्भुत रूसी लोक कथायें		
38. बच्चों सुनो कहानी!	लेव तोलस्तोय	85.00
39. जहां चाह वहां राह	उजबेक लोक कथाएं	175.00
40. पापा-जब बच्चे थे	अलेक्सांद्र रास्किन	170.00

### आर्डर भेजें:

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड  
5-ई, रानी झांसी मार्ग  
नई दिल्ली-110055  
दूरभाष: 011-23523349, 23529823  
ईमेल: pph5e1947@gmail.com  
<https://pphbooks.net>

### दिल्ली के शोरूम

जी-18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस  
नई दिल्ली-110001, फोन: 23324064  
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,  
नई दिल्ली-110067, फोन: 65447645  
पीपीएच शॉप, अजय भवन  
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली-2

नोट: आप भेज सकते हैं:

चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक मनिआर्डर "पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड" के पक्ष में

बैंक विवरण:

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

# गरीबों को घर मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा : भाकपा

पेज 16 से जारी...

सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं तो अधिकारी चुप रहते हैं। भाकपा नेता ने आरोप लगाया कि जब राज्य की जमीन पर गरीबों का कब्जा होता है तो वही अधिकारी तुरंत हरकत में आ जाते हैं।

राव ने कहा कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 2014 में अपने चुनाव अभियान के दौरान दलितों और आदिवासियों को तीन एकड़ जमीन देने का वादा किया था। केसीआर ने केजी से पीजी शिक्षा मुफ्त देने का भी वादा किया था, लेकिन वह उनमें से किसी को भी पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने

यह भी याद किया कि केसीआर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद वारंगल की अपनी पहली यात्रा के दौरान झुगियों में रहने वालों को डबल बेडरूम घर उपलब्ध कराने का वादा किया था, लेकिन यह आज तक भी पूरा नहीं हुआ। श्रीनिवास ने कहा कि भाकपा आश्रयहीन गरीबों को घर मिलने तक उनका समर्थन करती रहेगी। भाकपा वारंगल जिला सचिव मेकाला रवि, वरिष्ठ बुजुर्ग बुसा रविंदर, गुंडे बट्टी, जन्नु रवि, पी रमेश, टी रहेला, के नरसैय्या, बी रमेश, वेंकन्ना, देवराजू और स्वप्ना आदि अन्य लोग भी इस विरोध सभा में शामिल थे।



## हमारी आजादी को क्या खतरा...

पेज 1 से जारी...

बीच ईर्ष्या और वैमनस्य पैदा करती हैं। जातिवादी और भेदभावपूर्ण मनुस्मृति का झण्डा उठाते हुए आरएसएस ने अपने राष्ट्रविरोधी चरित्र को फिर से सिद्ध किया है।

हम, स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहे हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानियों की उन पीढ़ियों के लिए ब्रिटिश शासन से मुक्ति का क्या अर्थ था। उन्होंने किस उद्देश्य के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और एक स्वतंत्र भारत के लिए वे क्या चाहते थे। यह बार-बार रेखांकित किया जाना चाहिए कि गांधी, सुभाष बोस से लेकर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद तक, किसी ने भी एक धार्मिक हिंदू राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। वे सभी एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समतावादी और समावेशी भारत के लिए जिए और मरे। हमें उन मूल्यों की पहचान करनी चाहिए जिनका स्वतंत्र

भारत प्रतिनिधित्व करता है, उनकी भी जिन्होंने उनके लिए बलिदान दिया और उनकी भी जो उस स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थों को जानने के बाद उसके लिए खतरा बन रहे हैं। लोकतंत्र, धर्म निरपेक्षता और समानता हमारी स्वतंत्रता का आधार है और जो भी उसके लिए खतरा है वह सही मायने में राष्ट्र विरोधी है। विडंबना यह है कि ब्रिटिश कठपुतली अब स्वतंत्रता के अर्थ को फिर से परिभाषित करने और देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने की कोशिश कर रही है। इस प्रकार, यह हम पर है कि हम अपनी स्वतंत्रता को पहचानें और उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करें। एक समाज के रूप में, हमें उन तकलीफों पर फिर से विचार करना चाहिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए सही थीं और हमें उन तत्वों को अलग-थलग करने की जरूरत है जो उस स्वतंत्रता के लिए खतरा हैं।

## स्वामी सहजानन्द सरस्वती: 19वीं सदी...

पेज 11 से जारी...

दास टंडन, मोहन लाल गौतम, आचार्य नरेन्द्र देव आदि राष्ट्रीय स्तर के नेता सम्मिलित हुए। स्मरण रहे कि इससे पूर्व देश में किसानों का राष्ट्रीय स्तर का दूसरा संगठन नहीं था। आज भी स्वामी जी के संगठन का वारिस अखिल भारतीय किसान सभा देश के सभी राज्यों में संचालित है। इसीलिए 21 वीं सदी के प्रारंभ में अखिल भारतीय किसान सभा ने आजादी के लम्बे अन्तराल के बाद दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मेलन गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल में किया था। उस समय अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष पूर्व सांसद कामरुद चन्द्रपन तथा महासचिव अतुल कुमार अनजान थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जिस अखिल भारतीय किसान सभा का स्वरूप स्वामीजी ने पहली बार लखनऊ अधिवेशन में दिया था, उसका वास्तविक वारिस आज भी अखिल भारतीय किसान सभा उनके आदर्शों एवं सपने को साकार करने की दिशा में संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है।

अन्त में किसान सभा के बेजवाड़ा अधिवेशन में स्वामी जी के अध्यक्षीय भाषण के वाक्य उनकी आजीवन पीड़ा को व्यक्त करते हैं—“यह एक हृदय विदाकर तथ्य है कि ये किसान ही देवी-देवता, साधु-फकीर, भिक्षुक-नेता, पुलिस-मजिस्ट्रेट, उपदेशक अध्यक्ष, शासक और भूतपूर्व शासक, यहाँ तक कि मृत आत्माओं के लिए भी अपने घरेलू बजट में व्यवस्था करते हैं, लेकिन उनके लिए कोई रत्ती भर भी नहीं सोचता है।”

## लंदन की एक रात, हिंदोस्ता का नया ...

पेज 13 से जारी...

दुनिया की हर अच्छाई और दुनिया की हर बुराई इतिहास तक पहुंच गई है। नहीं, मैंने गलत कहा, मुझे यूँ कहना चाहिए हिन्दुस्तान में दुनिया की तमाम खूबियाँ अपनी हद तक पहुंचाई जा सकती हैं। लेकिन बुराईयाँ अपनी हद तक अभी से पहुंच गई हैं। तुमने बाज लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि हिन्दुस्तान में रूहानियत का बहुत जोर है। यह बिल्कुल झूठ है। रूहानियत के दो मानी हो सकते हैं। एक तो मादियत के बरखिलाफ यानी माद्री चीजों की परवाह न करना। दीनदारी, खुदापरस्ती, आखिरत की बातों को दुनियावी चीजों पर तरजीह देना।”

“और दूसरे मानी रूहानियत के क्या हैं? ” मैंने पूछा।

“दूसरे मानी रूहानियत के यह हो सकते हैं कि इसी दुनियावी जिन्दगी में लालच, हवस, दूसरों पर जब्रो-जुल्म करने की ताकत, जहालत, बदअक्ली, बददियानती को खत्म करना और जिंदगी के सोये हुए नगमों को जगाना, जिनके सुनने के लिए हमें एक बड़ा दिल, एक बेदार दिमाग और एक तंदुरुस्त जिस्म चाहिए। रूहानियत की दोनों किस्में हमारे यहाँ बिल्कुल मफकूद हैं।”

मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, “आप तो बड़े मादियतपरस्त बनते थे। आज रूहानियत का क्यों आप पर दौरा है?”

“मैं तो मादियतपरस्त हूँ, लेकिन वो इसलिए कि इंसान की जेहनी और रूहानी तरक्की को मुमकिन करने में मदद दूँ। आज जो लोग रूहानियत

का नाम लेते हैं, इनको इस चीज से कहीं दूर का भी तआल्लुक नहीं। रूहानियत है क्या? मजहब में डूबा हुआ दिमाग!” हीरेन कहने लगा, “तुम अखबारों में पढ़ती होगी कि हमारे यहाँ हिन्दू, मुसलमान और सिक्ख एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। मजहबी सवालालत की बिना पर। लेकिन इसके क्या ये मानी है कि उनमें रूहानियत या मजहबियत भरी हुई है? बिल्कुल नहीं! चंद महजबी लीडर जो भूलकर भी खुदा को याद नहीं करते गवर्नमेंट में रूतबे हासिल करने के लिए जिनमें सिर्फ उनका जाती फायदा है, जरा-जरा सी बातों पर बेकूसूर गरीब लोगों को मजहब का नाम लेकर आपस में लड़ा देते हैं। मजहब और रूहानियत से उनका कोई वास्ता नहीं।”

“रह गई दूसरी किस्म की रूहानियत। जो कौम गुलाम हो, जिसमें अस्सी फीसदी इंसानों को पेट भर खाना न मिलता हो, जिसमें मरज, वबा, बीमारी इस कदर फैली हो कि सारे मुल्क में मुश्किल से तंदुरुस्त इंसान नजर आते हों, जहाँ इल्म गिनती के लोगों तक महदूद हो, जहाँ बच्चे तक कुम्हलाए हुए फूलों की तरह हों, अक्सर लोगों के चेहरों पर भूख, फाका, गुरबत, मुसीबत लिखी हुई हो और बाकियों के चेहरों से सुस्ती, हिमाकत, जहालत और एक मकरूह किस्म की खुशहाली नजर आती हो, वहाँ जिंदगी के इन रंगीन तोहफों की तलाश करना सरासर हिमाकत है।”

हिन्दुस्तानी रूहानियत जिसको कि पूरी दुनिया में इज्जतो-ऐतबार,

एहताराम के साथ देखा जाता है, उस रूहानियत को जिस तरह मजहब, सियासत के ठेकेदारों ने अपने जाती फायदे के लिए इस्तेमाल किया, सज्जाद जहीर इसके बरखिलाफ थे। वे ऐसी रूहानियत पर कई सवाल उठाते हैं, जो इंसान को इंसान के हक छीनने पर मजबूर कर देती है। रूहानियत पर उनके पेश किए हुए नुक्ते आज भी हमें उतने ही मौजूब लगते हैं, जितने कि उपन्यास लिखने के समय। मादियतपरस्त होने के बावजूद उन्हें हिन्दुस्तानी रूहानियत और फलसफे से कोई गुरेज नहीं था, बल्कि वो उसे अवाम तक उसके हकीकी चेहरे-मोहरे में पहुंचाए जाने के हिमायती थे। सज्जाद जहीर एक लेखक में आजादी और लोकतांत्रिक अधिकारों की चेतना को सबसे अहम मानते थे। फिर वह चाहे किसी मजहब या विचारधारा का मानने वाला हो। उपन्यास ‘लंदन की एक रात’ दुनिया और उसकी तमाम मख्लूक की जिस्मानी और जेहनी आजादी, उनके हक और इंसाफ का अव्वलतरीन दस्तावेज है। अगर रूसो, वाल्टेयर, दिवेरो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के अगुआ थे, इटली में अंतोनियो ग्राम्शी का जो मुकाम है और रूस में जारशाही के खिलाफ पुश्किन, बेलिंस्की, तुर्गनेव, शोड्रिन, तालस्ताय, दोस्तोएवस्की, चेखव और गोर्की का अहम योगदान है, तो हिन्दुस्तान की आजादी में सज्जाद जहीर, तरक्कीपसंद तहरीक और उनके मुसन्निफीन के योगदान को नकारा नहीं जा सकता।

## गरीबों के घरों के लिए जमीन के संघर्ष के 100 दिन

## गरीबों को घर मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा : भाकपा

वारंगल, 9 अगस्त 2022: संघर्ष अपने 100वें दिन में दाखिल भाकपा के नेतृत्व में वारंगल में गरीबों हो चुका है। 9 अगस्त को निम्मीचेरुवु के लिए घर के लिए जारी जमीन का (मटेवाड़ा) के पास भुपोरटम (भूमि के

### बिहार में जदयू-महागठबंधन ने भाजपा को सत्ता से बाहर किया

जदयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़कर राज्य में नई सरकार बनाने के लिए महागठबंधन से हाथ मिलाया है। उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ 10 अगस्त, 2022 को शपथ ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री होंगे। वाम दलों-सीपीआई, सीपीआई (एम) और सीपीआई (एमएल) ने नई सरकार को समर्थन दिया है। वे सरकार में शामिल नहीं होंगे बल्कि बाहर से इसका समर्थन करेंगे।

भाकपा और माकपा के दो-दो विधायक हैं और भाकपा (माले) के 12 विधायक हैं। भाकपा महासचिव डी राजा ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को राज्य की कमान संभालने पर बधाई दी। अपने बधाई संदेश में, उन्होंने कहा: 'हमें उम्मीद है कि बिहार जन-समर्थक विकास का एक मॉडल पेश करेगा और धर्मनिरपेक्षता, हमारे संविधान और लोकतंत्र पर आरएसएस-भाजपा के हमले का मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता को बढ़ावा देगा।'

राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में एक समारोह में दोनों नेताओं को पद की शपथ दिलाई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद, जद (यू) और वाम दलों के प्रमुख नेता शामिल थे।

शपथ ग्रहण समारोह के बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि जल्द ही कैबिनेट के अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा की जाएगी।



लिए संघर्ष) के 100वें दिन के तेलंगाना सरकार के विरोध में बोलते हुए भाकपा सचिवमंडल सदस्य टी श्रीनिवास ने टीआरएस सरकार के पतन की भविष्यवाणी की और कहा कि भाकपा के नेतृत्व में भूमिहीन गरीबों द्वारा वारंगल में घरों के लिए भूमि का संघर्ष 100वें दिन में दाखिल हो चुका है। टीआरएस सरकार अपनी जनविरोधी नीतियों के कारण अपना

जनाधार खो रही है। श्रीनिवास ने कहा कि गरीब जो घरों के जगह या डबल बेडरूम वाले घरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे चुनावी वादे को पूरा करने में नाकाम सरकार के रवैये से परेशान हैं।

भाकपा नेता ने सरकार से 1 मई को भूमि पर कब्जा करने वाले आश्रयहीन गरीबों (सर्वेक्षण संख्या 126) को सरकार आदेश (जीओ)

58 के तहत भूमि पट्टा जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तीन महीने से अधिक समय हो गया है जब गरीब भूमि अधिकारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार को उनकी याचिका की चिंता ही नहीं है। उन्होंने सरकार पर अतिक्रमण पर आंख मूंदने का आरोप लगाया। जब रियल स्टेट कारोबारी शेष पेज 15 पर...

जनादेश का अपमान नहीं सहेंगे, जनादेश से देश चलेगा दल बदल से नहीं आदि आदि.....इन नारों की गूंज के बीच आज भक्त शिरोमणि के तेवर कुछ बदले बदले से थे। मैं उनसे बात करने की कोशिश में था और भक्त श्रेष्ठ थे कि उनकी व्याकुलता और उत्तेजना थमने का नाम नहीं ले रही थीं। वे नारे पर नारे दागे चले जा रहे थे। जैसे जैसे मैंने उन्हें शांत कराया और पूछा कि हे! भक्तों के सरताज आज ऐसी क्या मुसीबत आ गयी कि आप रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब भक्त ने पूरी तरह बौखलाहट में झल्लाकर चीखने के अंदाज में कहा कि जैसे तुम्हे मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ। यहां लोकतंत्र खतरे में पड़ा है और तुम कह रहे हो कि क्या हुआ। मैंने थोड़ा मासूमियत के अंदाज में पूछा क्यूं महाराज साहेब ने फिर किसी विपक्षी राज्य में सत्ता पलटवा दी क्या? अब भक्त का पारा सातवें आसमान पर था। उन्होंने हमलावर अंदाज में कहा कि तुम एक लोकतंत्र समर्थक और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकप्रिय नेता पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि बिहार में किस प्रकार जनादेश का अपमान हुआ है और मौकापरस्तों ने दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या कर डाली है।

अब मैंने भक्त शिरोमणि से कहा कि यह तो आपसी सहमति से एकसमान राजनीतिक सोच वाले लोगों का गठजोड़ है, एक सोच वालों का एक प्रकार का पुनर्मिलन है। इसमें जनादेश का अपमान कैसा। बिहार में राजद, जदयू ने पिछली

### साहेब आदेश : जनादेश

बार जब चुनाव लड़कर जीत हासिल की और बाद में जदयू भाजपा के साथ चला गया तब क्या जनादेश का अपमान नहीं था, महाराज? आक्रामकता बनाये रखते हुए भक्त ने कहा उसमें जनादेश का अपमान कैसा वह तो विकास के लिए गठजोड़ था, जनाकांक्षाओं के लिए गठजोड़ था। मैंने सवाल किया जनाकांक्षाओं के लिए गठजोड़ मतलब? भक्त ने कहा, अरे साधारण सी बात है, साहेब का अवतार देश के आम जन की आकांक्षाओं की पूर्ति और जनाकांक्षाओं को नयी उंचाईयों पर ले जाने के लिए हुआ है वो जो भी करते हैं, लोगों की जनाकांक्षाओं के मददेनजर ही करते हैं।

### बात-बेबात

अब उनसे गठजोड़ हुआ कि नहीं जनाकांक्षाओं से गठजोड़। मैंने भक्त से पूछा कि अब बिहार के सत्ता परिवर्तन में कैसी मौकापरस्ती उसमें तो कोई विधायक बंदी नहीं बनाये गये ना ही किसी दूसरे राज्य में कैद किये गये। यह तो सब शांति से संपन्न हो गया सत्ता परिवर्तन है। जनादेश के अपमान के तो आपके कीर्तिमान हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, अरुणाचल, गोवा, मणिपुर, महाराष्ट्र में तो दो दो बार के अनुभव आपको जनादेश लूटने के, सरकार गिराने और

बड़ी पार्टी होने के बावजूद विपक्ष को सरकार नहीं बनाने देने के हैं। भक्त ने कहा कि वही तो समस्या है। यह कोई सत्ता परिवर्तन नहीं जनादेश का अपमान है। सत्ता परिवर्तन तब होता है जब विधायकों को किसी भाजपा शासित राज्य के रिजार्ट में ले जाकर रखा जाये उन्हें राजनीतिक टूरिज्म का मौका दिया जाये। उनकी मनोभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें चार्टर्ड प्लेन की यात्राएं करवाई जाएं। कई जगहों होटलों की अदला बदली का आनन्दोत्सव मनाने का मौका दिया जाए। अब बताओ बिहार के विधायक ना मध्य प्रदेश गये, ना हरियाणा के रिजार्ट में पहुंचे और तो और करीब के असम में भी नहीं गये। कम से कम हिमंत विश्व सर्मा की विशेषज्ञता का लिहाज कर लिया होता, वह तो नजदीक ही थे। गोवाहटी तो दल बदल टूरिज्म का नवोदित केन्द्र था, वहां तो जाना ही चाहिए था। नवोदित दल बदल डेस्टिनेशन का ख्याल करके ही असम चले जाते उस नये गंतव्य की जीडीपी में कुछ सहारा लगता। देश में उत्तर पूर्व के नये नये बने चाणक्य की प्रतिष्ठा को भी चार चांद लग जाते। अब बिहार के राजनेता ठहरे विकास विरोधी कहां विकास के इन सूक्ष्मतरंग कारकों को समझें। उन्हें पता नहीं कि साहेब आदेश ही जनादेश है। जनाकांक्षाओं के प्रतीक लोकप्रिय नेता का आदेश स्वकेन्द्रित नहीं होता वह जन केन्द्रित होता है और इस प्रकार वही जनादेश होता है और बिहार की राजनीति ने तो साहेब के आदेशों का अपमान किया है। अब बताओ, बिहार में हुआ कि नहीं जनादेश का अपमान।